राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका
राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 4 ■ अंक 02 ■ दिसम्बर 2020 ■ ₹ 10 ■ पृष्ठ 36

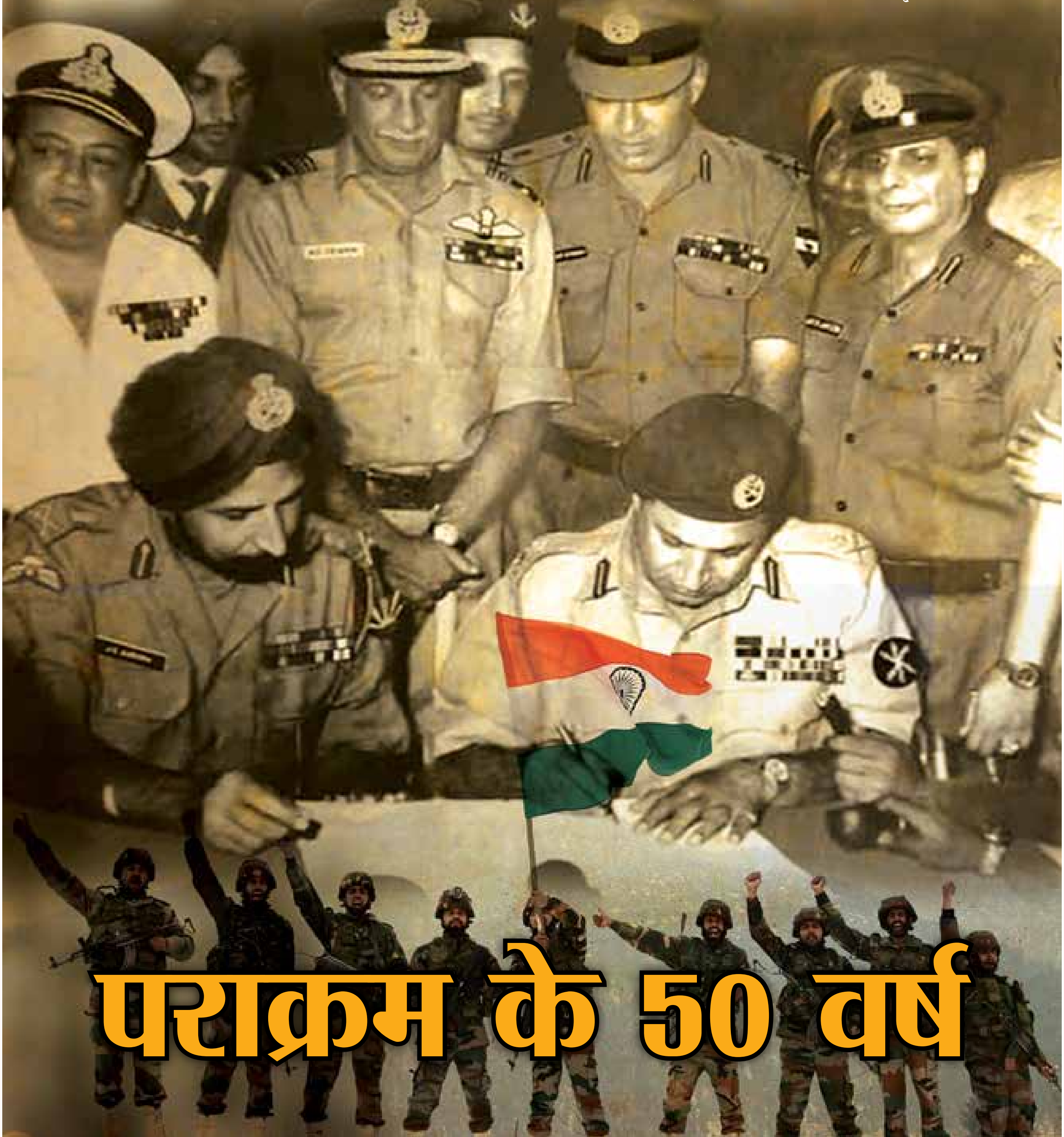

पराक्रम के 50 वर्ष

परिषद गतिविधियां

66 वें राष्ट्रीय अधिवेशन का पोस्टर विमोचन करते अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण, छात्रा प्रमुख प्रीति, नागपुर महानगर अध्यक्ष प्रा. श्रुति जोशी एवं मंत्री करन खंडाले

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर छात्रों को आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराता अभाविप प्रतिनिधिमंडल

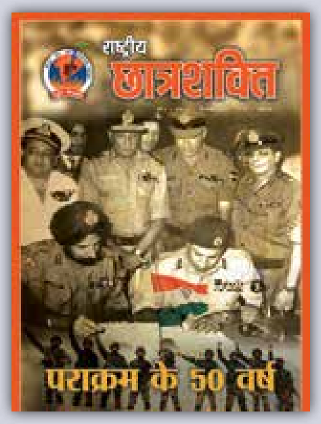

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 4, अंक 02
दिसम्बर, 2020

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक-मण्डल :
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रीत।

इस अंक में

05 **पराक्रम के 50 वर्ष**

भारतीय सेना ने यूं तो पाकिस्तान को कई बार धूल चटाये हैं चाहे 1947 हो,1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी परंतु पाकिस्तान है कि अपने नापाक इरादे से बाज नहीं आता ।16 दिसंबर को भारतवासी विजय दिवस के रूप में मनाता है। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शर्मनाक हार सामना...

संपादकीय	04
MANISH KUMAR (BACK2VILLAGE) AWARDED THE PRESTIGIOUS 'PROF. YASHWANTRAO KELKAR YOUTH AWARD 2020' FOR SUSTAINABLE FARMING INITIATIVE	11
CHHAGAN BHAI PATEL IS NEW ABVP PRESIDENT, NIDHI TRIPATHI CONTINUES AS NATIONAL GENERAL SECRETARY	12
विद्यार्थी परिषद-समसामयिक बदलाओं की स्वीकारोक्ति	13
बेगुसराय: अभाविप कार्यकर्ताओं ने लगाये 'नेकी की दीवार'	16
रोशनी एक्ट उर्फ़ जमीन जिहाद और गुपकार गैंग की फुफकार	17
काशी : अभाविप ने अंगवस्त्र देकर कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित	21
देश के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान: कटारिया	22
पुणे: आईआईएसईआर प्रशासन के खिलाफ अभाविप ने किया प्रदर्शन	23
FARMERS' STRIKE HAS NOTABLE LESSONS	24
अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भोलानाथ विज का निधन	26
हर दायित्व में मुझे कुछ नया सीखने को मिला: छगन भाई पटेल	27
कड़कड़ाती ठंड के बीच दिन-रात 9 दिन चला अभाविप का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन	28
अभाविप महाकौशल प्रांत द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन	29
अभाविप के विरोध के बाद तमिलनाडु के एमएसयू विवि ने पाठ्यक्रम से अरुंधति रॉय की पुस्तक हटायी	30
यह पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है: मनीष कुमार	31
नहीं रहे अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओव्हाल, कार्यकर्ताओं में शोक की लहर	32
भगवान बिरसा को अभाविप ने जनजाति गौरव के रूप में किया याद, देश भर में कार्यक्रम का आयोजन	33
ग्वालियर: विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली छात्राओं को अभाविप ने किया सम्मानित	34

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन गत वर्ष आगरा में हुआ तो अनेक स्तरों पर विविध कार्यक्रमों की योजना बनी थी। उनकी पूर्ति के लिये आगे बढ़ना प्रारंभ ही किया था कि विश्वव्यापी आपदा के रूप में कोरोना प्रकट हुआ। कोरोना के पीड़ितों की सेवा–सहायता का दुष्कर कार्य भी परिषद कार्यकर्ताओं के जिम्मे आ गया।

परस्पर मिलना–जुलना, कार्यक्रमों के लिये एकत्र होना प्रतिबंधित, स्कूल–कॉलेजों में अवकाश और अनिश्चितता का वातावरण। रोजगार खो चुके साधनविहीन लोग हजारों की संख्या में पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। मानवनिर्मित विभीषिका का यह त्रासद रूप था। समाज के सहयोग से संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति को सेवा कार्यों में लगा दिया। व्यथित मजदूरों के भोजन–स्वास्थ्य आदि की चिन्ता करने के साथ ही एक समय के बाद स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी बाधित न हो इसलिये कार्यकर्ताओं ने बस्तियों में जाकर पाठशालाएं चलानी शुरू की।

किसी भी छात्र–संगठन से इस प्रकार की गतिविधियों की आशा विश्व में कहीं नहीं की जाती किन्तु "आज का छात्र–आज का नागरिक" की संकल्पना देकर परिषद ने आज के प्रश्नों पर रचनात्मक हस्तक्षेप को अपनी कार्यपद्धति में शामिल किया। इस नीति के चलते ही अभाविप के कार्यकर्ता प्राकृतिक अथवा मानवनिर्मित किसी भी आपदा के समय अग्रिम पंक्ति में सेवारत दिखे।

इस बीच प्रौद्योगिकी का सफल प्रयोग करते हुए न केवल सांगठनिक गतिविधियों की निरंतरता को बनाये रखा गया अपितु वेब माध्यमों का उपयोग कर वैचारिक प्रबोधन के भी बहुविध प्रयास हुए। बड़ी संख्या में वेब संगोष्ठियों के माध्यम से कार्यकर्ता विकास प्रक्रिया को गति दी गयी तथा सामान्य विद्यार्थियों को राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विमर्श में सहभागी किया गया।

कोरोना के प्रकोप से पूरी तरह से बाहर आने के पूर्व ही कुछ राजनैतिक दलों तथा अराजक तत्वों की दुरभिसंधि के चलते उत्तेजित किसान पहले रेल पटरियों पर और बाद में दिल्ली की सीमाओं पर आ डटे। यद्यपि पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़ कर अपने इरादों में इन्हें सफलता नहीं मिली किंतु अपनी रणनीति के तहत उन्होंने इसे वैधानिक प्रावधानों में अपेक्षित सुधारों के बजाय किसान स्वाभिमान का विषय बना दिया है। तमाम कठिनाइयों तथा विपरीत मौसम के बीच भी किसान संयम बनाये हुए हैं किन्तु परदे के पीछे से काम करने वाली इन शक्तियों को किसानों का धैर्य टूटने का इंतजार है ताकि उनकी आड़ में वे पिछले वर्ष हुए सीएए के विरुद्ध आंदोलन जैसी किसी घटना को दोहरा सकें। निस्संदेह इसका सर्वस्वीकार्य हल निकाल कर इस प्रकरण को समाप्त करना होगा।

इस वर्ष जहाँ हमें श्री भोलानाथ विज और श्री हेमन्त विश्नोई जैसे अनेक पूर्व कार्यकर्ताओं का वियोग सहना पड़ा वहीं ऊर्जावान कार्यकर्ता और वर्तमान में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे अनिकेत ओव्हाल भी हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्‌गति प्रदान करे।

सीमित संख्या का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में होने जा रहा है जिसमें नयी परिस्थिति में नयी कार्ययोजना बनेगी।

युवादिवस की हार्दिक शुभकामना सहित

आपका
संपादक

पराक्रम के 50 वर्ष

फोटो साभार: गूगल

| अजीत कुमार सिंह |

भारतीय सेना ने यूं तो पाकिस्तान को कई बार धूल चटाये हैं चाहे 1947 हो,1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी परंतु पाकिस्तान है कि अपने नापाक इरादे से बाज नहीं आता । 16 दिसंबर को भारतवासी विजय दिवस के रूप में मनाता है। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शर्मनाक हार सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। 1971 में भारत – पाक के बीच हुआ युद्ध एक सैन्य संघर्ष था, जिसका आरंभ तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम के कारण 3 दिसंबर, 1971 से हुआ जिसका समापन 16 दिसंबर 1971 को ढाका समर्पण के साथ हुआ। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुआ जिसके जवाब में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम के समर्थन में कूद पड़ी। मात्र 13 दिन तक चलने वाले इस युद्ध ने इतिहास के साथ – साथ पाकिस्तान का भूगोल भी बदल दिया। युद्ध के दौरान नापाक मंसूबो वाले पाकिस्तानी सेनाओं का सामना भारत के पराक्रमी योद्धाओं के साथ एक साथ पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों छोरो पर हुआ। जल, थल और नभ तीनों तरफ से भारतीय सेना काल की तरह पाक सैनिकों पर बरस पड़े। इस युद्ध में 39 सौ भारतीय सैनिक वीरगति प्राप्त हुए एवं 9851 सैनिक घायल हुए थे लेकिन भारतीय सैनिकों के शौर्य का ही परिणाम था कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने करीब 93 हजार सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर हथियार डाल दिये थे।

मुक्ति वाहिनी

पश्चिमी पाकिस्तान की बर्बरता और रक्तपात से जन्म

युद्ध की पृष्ठभूमि

बांग्लादेश रूपी देश के उदय की नींव 25 फरवरी 1948 को ही रख दी गई थी जब पाकिस्तानी संसद में उर्दू और अंग्रेजी के साथ बांग्ला को भी मान्यता देने की बात चली। तत्कालीन प्रधानमंत्री लिकायत अली खान ने तुरंत ही इस बात को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि बांग्ला को मान्यता देने की बात का मजाक भी उड़ाया। यह कोई समान्य घटना नहीं थी, बल्कि यहीं से शुरुआत हुई एक नये देश के जन्म की...।

शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्ता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए छह सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर था। इसी बीच पाकिस्तान में 1970 में चुनाव हुए। 1970 का यह चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबर्दस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबर्दस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को नियंत्रित कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और सैन्य शासन को मुजीब को सत्ता सौंपना नागवार गुजरा। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। आंदोलन की आवाज को दबाने एवं जनभावना को कुचलने के लिए शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में नायक बन गए। मार्च, 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया।

हुआ मुक्ति वाहिनी का। 1969 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अयूब के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया था और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में यह अपने चरम पर था। मुक्तिवाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्तिवाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। पाकिस्तान की अस्थिरता का असर भारत पर भी पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से लोग भागकर भारत आने लगे। माना जाता है कि उसी दौर में लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आए। ज्यादातर शरणार्थी हिंदू थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस मामले को वैश्विक पटल पर उठाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्वी पाकिस्तान में जनसंहार जारी था। लगातार विस्थापन और क्रूरता को देखते हुए 29 जुलाई, 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से मुक्तिवाहिनी की मदद करने की घोषणा की गयी। तीन दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। इसके साथ ही 1971 के भारत-पाक युद्ध की शुरुआत हो गयी।

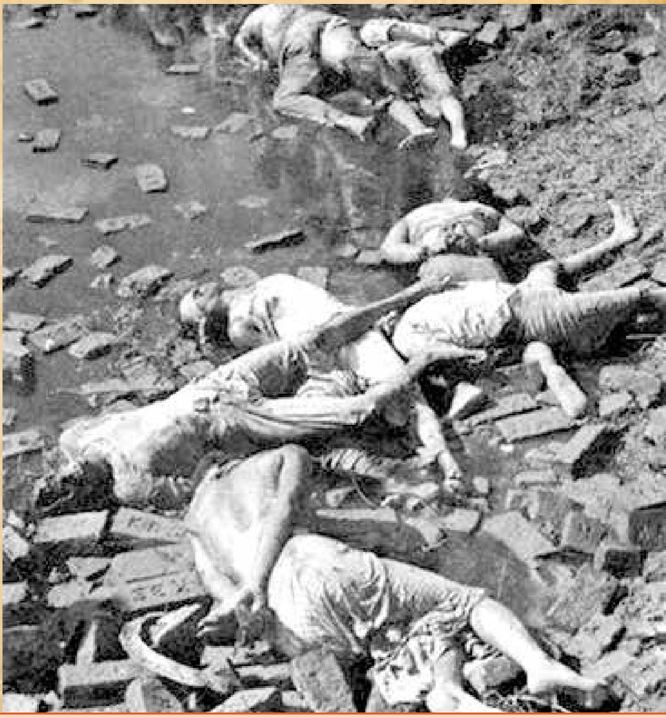

पाक सेना के बर्बरता की अनकही दास्तां

उचित मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों को शांत कराने के बजाय पाक सरकार जनसंहार पर उतर आई। पूर्वी पाक के लोगों को भारत का एजेंट कहा जाने लगा और 'ऑपरेशन सर्चलाइट'चलाकर उन्हें मारने का अभियान चल पड़ गया। बेबस, लाचार और निहत्थे मासूम लोगों को उनके घर से निकाल – निकालकर मारा जाने लगा। हत्या और बलात्कार की इंतहा हो गई। महिलाओं की अस्मत को सरेआम लूटी गई।बड़ी संख्या में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों को गोलियों से भून दिया गया। आज भी ढाका मस्जिद के पास एक बड़ी सी कब्र है जिसमें दफ्न हजारों लाशें उस दौर का स्मारक है। पूर्वी पाकिस्तान की गलियां चीख, चीत्कार से कराह उठी। जानकार बताते हैं कि 1971 के मुक्ति संग्राम के समय पूर्वी पाकिस्तान के महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार किया गया और हत्या की गईं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग चार लाख महिलाओं के साथ बलात् यौन संबंधों को बनाना, सैनिक कैण्ट में महिलाओं को सेक्स वर्कर के रूप में रखना आदि सामूहिक बलात्कार जैसी हरकतें थीं। 563 बंगाली महिलाओं को पहले दिन से डिंगी

फोटो साभारः गूगल

मिलिट्री कैंट में कैद कर दिया गया था। इन महिलाओं के साथ पाकिस्तानी सेना के जवान ज्यादतियां करते थे। अत्याचारों से परेशान होकर लगभग एक साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब एक करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत में शरण ले ली।

भारत पर हमला युद्ध की शुरुआत

पूर्वी पाकिस्तान के संकट ने विस्फोटक रूप ले लिया, पाकिस्तानी हुकूमत की हालत खराब होने लगीं। नवंबर 1971 के माह भर पाकिस्तानी रूढ़िवादी – कट्टरपंथियों के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े – बड़े मार्च होने लगे और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की जाने लगी। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी और अपने लोगों को को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 3 दिसंबर (1971) की शाम लगभग 05:40बजे, पाकिस्तान वायुसेना ने भारत – पाक सीमा से 300 मील दूर बसे आगरा समेत उत्तर – पश्चिमी भारत के 11 वायुसेना स्टेशन पर अप्रत्याशित रिक्ति – पूर्व हमले कर दिये। उसी शाम, राष्ट्र के नाम संदेश में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हवाई हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से भारत पर युद्ध की घोषणा हैं और उसी रात को भारतीय वायुसेना ने पहली जवाबी कार्रवाई भी कर दी। अगले दिन ही इन जवाबी हमलों को बड़े स्तर पर आक्रमण में बदल दिया गया। पाकिस्तान के हवाई हमले के साथ ही युद्ध की शुरूआत हो गई। भारत सरकार ने सेना की टुकड़ियों को सीमा की कूच करने के आदेश दिये तथा इस अभियान में समन्वय बनाकर जल, थल और नभ से पाकिस्तान पर सभी मोर्चों पर हमले बोल दिये गए।

वायु हमला

पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये हवाई हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने रौद्र रूप ले लिया और पूर्वी पाकिस्तान पर जबरदस्त पकड़ बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान पर पकड़ मजबूत होने के बाद भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर अपने हमले को जारी रखा। यह हमला अब दिन में विमान भेदी तोपों, रडार भेदी

विमानों एवं लड़ाकू जेट विमानों के पास – पास से होने वाले हमलों की तथा रात के समय में विमानक्षेत्रों हवाई पट्टियों, हवाई स्टेशनों पर हमलों तथा पाकिस्तानी बी – 57 व सी – 130 और भारतीय कॉनबर व एएन – 12 के बीच भिड़तों की शृखंला में बदलता जा रहा था। पाकिस्तान के एयर फोर्स ने अपने एयर बेसेज की आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षात्मक गश्ती दल हेतु एफ – 6 तैनात करने शुरू किये परंतु बेहतर एयर क्वालिटी के अभाव के कारण वह प्रभावी आक्रामक अभियान नहीं चला पा रहा था। भारतीय वायुसेना ने एक संयुक्त राज्य वायुसेना एवं एक संयुक्त राष्ट्र विमान को ढाका में नष्ट कर दिया एवं इस्लामाबाद में कनाडा के रॉयल कनाडा वायुसेना के डीएचसी-4 कॅरिबोउ के साथ खड़े हुए सं.राज्य मिलिट्री के सम्पर्क प्रमुख ब्रिगेडियर-जनरल चुक यीगर के निजी सं.राज्य वायुसेना से लिये हुए बीच यू-8 सहित दोनों को उड़ा डाला। हमलों में बुरी तरह मात खाने एवं भारतीय हमलों में हानि के बाद पाकिस्तान ने रक्षात्मक रुख अपना लिया। भारतीय वायुसेना ने लगभग 4000 से अधिक उड़ानें भरीं जबकि पाक वायुसेना ने उसकी जवाबी कार्रवाई नामलेवा ही की। भारत के मुकाबले पाक वायुसेना युद्ध के प्रथम सप्ताह तक महाद्वीपीय आकाश से विलुप्त हो चली थी। अगर कुछ पाक सेना विमान बचे भी थे, उन्होंने या तो ईरानी एयरबेस में शरण ली या कंक्रीट के बंकरों में जा छिपे एवं आगे कोई हमला करने का हिम्मत नहीं जुटा पाये।

कश्मीर को पंजाब से काटने की नापाक साजिश पर जब फिरा पानी

पाकिस्तान ने कश्मीर को पंजाब से काटने की गहरी साजिश रची थी। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को पंजाब से अलग करने के लिए शकरपुर में बसंतर नदी पर अपने सैन्य बलों का अभेद्य किले जैसा जमावड़ा कर लिया था। भारतीय सेना के पास एक ही रास्ता बच गया था कि वह बसंतर नदी को पार करके पाकिस्तान की सीमा में सेंध मार दुश्मनों के हौसलों को पस्त करे। पाकिस्तान ने अपने 10 टैंक तैनात किये थे और उसके10 टैंकों के सामने भारत तीन टैंक दीवार बन कर खड़े थे। एक टैंक पर लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल थे। भारत ने पाकिस्तान के 7 टैंक नष्ट कर दिए थे, लेकिन दो टैंकों को लीड करने वाले घायल हो चुके थे। सारी जिम्मेदारी अरुण क्षेत्रपाल के कंधो पर आ गई थी। क्षेत्रपाल के टैंक में भी आग लगी हुई थी। उन्हें आदेश मिला कि वे वापस आ जाएं। अरुण क्षेत्रपाल ने वायरलेस बंद किया और अकेले ही मुकाबला करने का फैसला किया और बहादूरीपूर्वक दुश्मन के दो टैंक उड़ा दिए, लेकिन तभी एक गोला उनके टैंक पर आकर गिरा और वे बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तान का आखिरी टैंक उनसे कुछ ही दूरी पर था। आमने-सामने के हमले में वीर सपूत अरुण क्षेत्रपाल ने दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करते हुए अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं।

भूमि आक्रमण

पूर्वी पाकिस्तान की संकट को देखते हुए युद्ध के पूर्व ही भारत की सेनाएं दोनों मोर्चों पर सुव्यवस्थित थीं साथ ही पाक सेना की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या भी अधिक थी। भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमाओं में घुस कर मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। भारत की 9 पैदल सेना टुकड़ियों के साथ बख्तरबंद इकाइयों एवं इनके सहायक वायु हमलों के साथ भारतीय सेनाओं ने शीघ्र ही पूर्वी पाकिस्तान की तत्कालीन राजधानी ढाका तक पहुंच बनायी। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के लेफ़्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पूर्वी पाकिस्तान पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया, जिनकी सहायता में भारतीय वायुसेना ने तेज गति से पाकिस्तानी पूर्वी कमान के उपस्थित छोटे-छोटे हवाई दलों को नष्ट कर डाला जिससे ढाका वायुक्षेत्र का प्रचालन एकदम प्रभावित हो गया। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर अधिकार जमाने में सफल हुए तथा शीघ्र ही लगभग 5,795 वर्ग मील (15,010 कि.मी.) पाक भूमि अपने अधीन ली जिनमें पाक अधिकृत कश्मीर, पंजाब एवं सिंध के क्षेत्र आते हैं, किन्तु बाद में 1972 के शिमला समझौते के अन्तर्गत्त सद्भावना के रूप में वापस कर दिये गए। भारत ने इस युद्ध में "ब्लिट्ज़क्रीग" तकनीकें अपनायी, जिसके अन्तर्गत्त शत्रु के स्थानों में कमजोरी व्याप्त कर, उनके विरोध से बचते हुए शीघ्रता से विजय प्राप्त की।

जब काल बनकर पाकिस्तान पर बरस पड़े भारतीय नौसैनिक

पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय नौसेना की तरफ से चार दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया। नौसेना ने दोनों मोर्चे पूर्वी पाकिस्तान(बंगाल की खाड़ी) और पश्चिमी पाकिस्तान(अरब सागर) पर अपनी मजबूत तैयारी के साथ मैदान में था। पश्चमी मोर्चे का नेतृत्व नौसेना पोत मैसूर से एडमिरल कुरुविल्ला और वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली कर रहे थे। तीन – चार दिसंबर की रात में भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के पीएनएस खैबर को डूबो दिया इसके अलावा माइंस स्वीपर पीएनएस मुहाफिज, पीएनएस शाहजहां को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया जिसमें मरने और जख्मी होने

फोटो साभार: गूगल

वाले पाकिस्तानी नौसेनिकों की संख्या करीब 720 थी। नौ दिसंबर को भारत को सबसे बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस हंगोर ने भारत के आईएनएस खुकरी को अरब सागर में डूबो दिया, जिसमें 194 भारतीय हताहत हुए। इसके जवाब में ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद भारत ने आठ – नौ दिसंबर को ऑपरेशन पायथन शुरू किया,जिसके तहत भारत के मिसाइल जहाजों ने पुनः कराचीं पोर्ट पर हमला किया और पाकिस्तान के रिजर्व फ्यूल टैंक के साथ – साथ पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर को तहस – नहस कर दिया। इस हमले में उसके तीन मर्चेंट जहाज डूब गए । कराची पोर्ट भी कई दिनों तक जलता रहा।

वहीं पूर्वी तट का मोर्चा वाइस एडमिरल कृष्णन ने संभाल रखा था, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अवरोध बनाकर पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से काट दिया। जिस कारण पूर्वी पाकिस्तानी नौसेना एवं आठ विदेशी व्यापारिक जहाज भी वहीं पर फंसकर रह गये।आईएनएस विक्रांत की मदद से सी – हॉक फाइटर बॉम्बर ने पूर्वी पाकिस्तान के तटीय इलाकों में हमले किये। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना सबमरीन गाजी को भेजा जो विशाखापत्तनम कोस्ट के पास डूब गया, जिसमें 96 पाकिस्तानी सैनिक थे। भारत के आईएनएस राजपूत ने इसे नष्ट कर दिया जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। हालांकि इस तट पर भारत को भी नुकसान हुआ।

जनरल नियाज़ी का आत्मसमर्पण और बाग्लादेश का उदय

16 दिसंबर 1971 ही वह स्वर्णिम दिन था जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। आधिकारिक रूप से 16 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना के कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने रेसकोर्स, ढाका में समर्पण अभिलेख पर हस्ताक्षर किया। दरअसल पूर्वी तट पर मजबूत पकड़ के बाद भारतीय सेना ढाका कूच कर गई थी। जगजीत सिंह अरोड़ा भारतीय सेना के कमांडर थे। ढाका में तीस हजार पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे और जनरल अरोड़ा के पास करीब चार हजार सैनिक, दूसरे सैन्य दलों का पहुंचना अभी बाकी था। भारतीय कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से मिलने पहुंचे और ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाब डाला कि नियाजी को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा। समर्पण होने के बाद भारतीय सेना ने लगभग 93 हजार सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक का सबसे बड़ा समर्पण था। 16 दिसंबर 2021 को

भारतीय सेना के पराक्रम के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

स्वर्णिम विजय के अमिट हस्ताक्षर

हर युद्ध की तरह 1971 के युद्ध में भी सेना के हजारों जवानों ने वीरता का परिचय दिया लेकिन इनमें कुछ ऐसे नाम थे जो स्वर्णिम विजय के अमिट हस्ताक्षर बन गए। इन पराक्रमी योद्धाओं में सबसे पहला नाम अलबर्ट एक्का का आता है जिन्होंने अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई। अल्बर्ट एक्का ने अपनी बटालियन 'द ब्रिगेड ऑफ द गार्डस' के साथ ईस्टन फ्रंट डिफेंस के दौरान गंगासार में दुश्मनों पर हमला किया। अल्बर्ट ने देखा कि बंकर से एक दुश्मन एमएमजी की मदद से उनकी टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने उस बंकर पर हमला बोल दिया और उसकी जान ले ली। इस दौरान एक्का बुरी तरह जख्मी हो गये। एक अन्य दुश्मन ने इनकी टीम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अल्बर्ट एक्का खून से लथपथ थे फिर भी हाथ में ग्रेनेड लेकर उस दुश्मन पर हमला बोल दिया। तीन दिसंबर को उन्होंने अपने प्राण गंवा दिये। वीरगति के बाद सरकार ने सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा। दूसरा नाम था मेजर होशियार सिंह का जिन्होंने तीन ग्रेनिडियर्स की अगुवाई करते हुए अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया, उन्होंने जम्मू – कश्मीर की दूसरी ओर शकरगड के पसारी क्षेत्र में जरवाल का मोर्चा फतह भी किया, उन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। तीसरा नाम हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जिन्हें 4 दिसंबर की शाम को सूचना मिली की बड़ी संख्या में दुश्मन की फौज लोंगेवाला चौकी की तरफ बढ़ रही है। उस समय लोंगेवाला पोस्ट पर मात्र 90 भारतीय जवान थे। 29 जवान और लेफ्टिनेंट पेट्रोलिंग कर रहे थे. आदेश मिला कि या तो दुश्मन का सामन करें या फिर पैदल रामगढ़ के लिए रवाना हो जाएं।मेजर चांदपुरी ने दुश्मन के साथ दो-दो हाथ करने की ठानी। उनका लक्ष्य था कि किसी तरह पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ने से रोका जाए। अंधेरा घिर आने पर पाकिस्तानी टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट को घेर लिया। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई इतनी दमदार थी कि पाकिस्तान सेना कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। चांदपुरी के नेतृत्व में चंद जवानों ने पाकिस्तान के हजारों जवानों के हौसले पस्त कर दिए थे।

हर युद्ध की तरह 1971 के युद्ध में भी सेना के हजारों जवानों ने वीरता का परिचय दिया लेकिन इनमें कुछ ऐसे नाम थे जो स्वर्णिम विजय के अमिट हस्ताक्षर बन गए। इन पराक्रमी योद्धाओं में सबसे पहला नाम अलबर्ट एक्का का आता है जिन्होंने अपनी क्षमता से बाहर जाकर देश को विजय दिलाई।

कैप्टन महेन्द्र नाथ मुल्ला ने तो देश की रक्षा करते – करते जल समाधि ले ली। बात 6 दिसंबर 1971 की है। 6 दिसंबर को भारतीय नौसेना को संकेत मिले कि एक पाकिस्तानी पनडुब्बी 'हंगोर' भारतीय सीमा में आ गई है। नौसेना मुख्यालय ने आदेश दिया कि भारतीय जल सीमा में घूम रही इस पनडुब्बी को तुरंत नष्ट किया जाए और इसके लिए एंटी सबमरीन फ्रिगेट आईएनएस खुखरी और कृपाण को भेजा गया। पाकिस्तानी 'हंगोर' ने पहला टॉरपीडो कृपाण पर चलाया, लेकिन फट नहीं पाया। इसके बाद खुखरी पर हमला किया गया। खुखरी पर दूसरा धमाका होते ही पूरे पोत की बत्ती चली गई। कैप्टन मुल्ला ने देखा कि खुखरी में दो छेद हो चुके हैं और उसमें तेजी से पानी भर रहा है। फनल से लपटें निकल रही थीं। जहाज पर सवार अन्य जवान जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े, लेकिन कैप्टन मुल्ला ने वहीं डटे रहने का फैसला किया। खुखरी के डूबते समय जहाज टूट गया। कैप्टन मुल्ला जहाज के इस मलबे के साथ जल समाधि में लीन हो गए।

1971 के स्वर्णिम विजय गाथा के नायकों की सूची लंबी है। इस कड़ी में लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ, कमांडर ले. जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, निर्मलजीत सिंह सेखों, चेवांग रिनचैन जैसे कुछ और प्रमुख नाम हैं जिन्होंने इस युद्ध में पाक को करारी हार देकर विजय की नई परिभाषा गढ़ी। ■

Manish Kumar (Back2Village) awarded the prestigious 'Prof. Yashwantrao Kelkar Youth Award 2020' for sustainable farming initiative

The Selection Committee for the Prof Yashwantrao Kelkar Youth Award 2020 has approved the name of Shri Manish Kumar, resident of Vaishali (Bihar). He has been awarded for 'Attracting Youth Towards Sustainable Organic and Multi-Pronged Farming and Creating Rural Employment Through Enterprises by Skilling Youth'. He will be conferred with the award in the 66th National Conference of ABVP scheduled to be held in Nagpur.

This award is given in the memory of Prof Yashwantrao Kelkar since 1991, who is remembered as the architect of the organization and for his role in its expansion. The Award is a joint initiative by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and Vidyarthi Nidhi Nyas, which is committed to betterment of students and working in the field of education.

Manish Kumar will be awarded the Yuva Puraskar for the year 2020 at the 66th National Conference (25-26 December, 2020) of ABVP, to be held at Nagpur (Vidarbha) on 26th December, 11:30 AM during the Prof. Yashwantrao Kelkar Youth Award ceremony. The Award aims to the highlight the work of young social entrepreneurs, to encourage them and to express the youth's gratitude towards such social entrepreneurs, inspiring young Indians. The Awardee is awarded with Rs. 1,00,000/- cash, certificate and memorabilia.

Manish Kumar, a native of Vaishali (Bihar), spent his childhood across several small towns of Bihar and often visited his native village with his family. He finished his post-graduate degree (Integrated Masters) from IIT Kharagpur in 2010 and got placed in a large US-based multinational software company. However, he rejected the job offer and instead focused his energies on rural development work. Starting from his native village in 2010 he co-founded Farm & Farmers and now being the co-founder runs 'Back to Village (B2V)', a non-profit organisation focused on organic farming and farming-centric comprehensive rural development aimed at making villages prosperous and self-reliant. He continues to work with the belief that the condition of rural and tribal communities can be improved only by creating local agro-centric and agro-allied livelihood opportunities, which will increase their earning capacities and also contribute to the improvement of basic facilities in villages. He is running various successful models in Odisha, Jharkhand and Bihar.

While the farmers are still struggling to smoothly access basic inputs like quality seeds, soil, sufficient water or basic farming techniques, the educated youth are unwilling to choose agriculture as their primary occupation. The Unnat Krushi Kendra (UKK), as part of the B2V initiative, aims to bridge this knowledge gap by forming groups of young, educated people across villages and provide training as well as assistance to enable them to earn decent livelihoods. UKK promotes organic farming by providing end-to-end services to farmers. With services ranging from crop selection to training and crop monitoring to the market linkage, more than 5000 farmers hailing from the tribal-dominated areas of Mayurbhanj (Udala, Khunta and Kaptipada), Balasore (Nilagiri) and Puri (Kanas) have benefitted under this initiative.

Hundreds of tribal farmers from Mayurbhanj, Koraput, Kandhamal, Raygada,

Nayagarh were trained in value addition and marketing of agro products like jackfruit, ginger, turmeric, coffee, lemongrass, palmarosa, sal leaf, millet and indigenous seeds, 75 enterprising tribal youth, identified and trained in agro-entrepreneurship skills, subsequently commenced their agro-businesses to assist local farmers.

Manish Kumar has also undertaken the 'Urban Farming' initiative which explores cultivation techniques suitable for urban environments including one's residential building.

ABVP National President Dr Subbiah Shanmugam, ABVP National General Secretary Nidhi Tripathi have conveyed their greetings to the awardee and wished him success in his future endeavours. ■

Chhagan Bhai Patel is new ABVP president, Nidhi Tripathi continues as national general secretary

The ABVP has unanimously elected professor Chhagan Bhai Patel from Gujarat as its president. Meanwhile, Delhi's Nidhi Tripathi remains the national general secretary of the Akhil Bharatiya Vidyarathi Parishad..

The announcement was made on Tuesday from the ABVP central office in Mumbai. According to the statement issued by Election Officer Dr. Uma Shrivastava, the tenure of both the posts will be one year and both the elected representatives will assume office in the 66th National Session of December 25-26, in Nagpur.

Patel, 55, is originally from Mahesana district of Gujarat. A Phd in Pharmacy, a Professor and Principal in 'Sarvajanik Pharmacy College' of Mahesana, Patel founded the Faculty of Pharmacy of Gujarat Technical University.

"Since 1996, he has served for technical education and as city vice president, city president and state vice president. He was President of ABVP Gujarat State from the year 2013 to 2016 and National Vice President from the year 2016 to 2019," said a statement from ABVP profiling him.

Meanwhile, Nidhi Tripathi, 27, who holds her position this time as well, is a product of Jawaharlal Nehru University. Earlier, she represented ABVP as the presidential candidate in the JNU Students Union Election in 2017. Back in 2016, she was at the forefront of the counter-protest against the alleged anti-India slogans raised in JNU that created headlines. ■

विद्यार्थी परिषद–समसामयिक बदलाओं की स्वीकारोक्ति

| विक्रांत खंडेलवाल |

विद्यार्थी परिषद की विकास यात्रा के गत 70 वर्षों के सफर को 30 वर्षों से निकट से देखने और शेष के बारे में सुनने – पढ़ने का स्वर्णिम अवसर मुझे मिला है। किसी भी संगठन अथवा संस्था की जींवत्ता यही होती है कि आप समयानुकूल बदलावों को स्वीकार करते - करते आगे बढ़ें और जहां नित्य नूतन, नव सृजन की ताजी बयार बहती हो वहां यह बदलाव और ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों, युवाओं को साथ लेकर शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत संगठन है। इसलिए प्रतिवर्ष हजारों विद्यार्थी ,शिक्षक परिषद में जुड़ते हैं। व्यक्तित्व विकास के विविध आयामों में अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं ।एक जिम्मेदार सजग नागरिक बनकर समाज जीवन के विविध कार्यों में सहभागी होते है कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद व्यक्तित्व निर्माण की सहज सुलभ जीवंत पाठशाला है।

गत सात दशकों की विकास यात्रा में 2019 -20 में आयी कोरोना महामारी ने वैसे तो पूरी दुनिया को हिला दिया है। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन कर सामने आयी है लेकिन हम सभी ये भी महसूस करते हैं कि एक तरफ इस काल ने हमें अपनी पुरानी परंपराओं, मान्यताओं, रहन – सहन, खान – पान तथा शुद्ध वातावरण में व्यवस्थित दिनचर्या के साथ न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करते हुए जीवन – यापन करना सिखाया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया को आधुनिकतम तकनीक का सदुपयोग करवा हमारी आदतों में शामिल करवाया है ताकि हम हर स्थिति में चलते रहें, हमारा काम न रूके, हमारा विकास अवरूद्ध न हो। और इस चुनौती को विद्यार्थी परिषद जैसे जीवंत संगठन ने अवसर में बदलते हुए अपने नीति, नियमों, सिद्धांतों तथा कार्यपद्धति की मूलभूत बातों में पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा रखते हुए कार्यक्रमों के लिए आवश्यक साधन और माध्यमों में बदलाव को स्वीकार कर आगे की चल पड़े। जैसे –

1. रचनात्मकता का विस्तार – वैसे तो विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से ही अपने कार्यकर्ता में रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला वर्ष भर चलाती है, जिसमें विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां, सेमिनार, संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन होता है लेकिन कोरोनाकाल में घर बैठे इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन अथवा उसमें आगे बढ़कर ऑनलाइन माध्यमों से वेबीनार प्रतियोगितायें, बौद्धिक वर्ग, संगठनात्मक बैठकें, विविध विषयों पर सम्मेलनों का आयोजन, फोन पर संपर्क अभियान जो किया गया है, अनुकरणीय है। हमलोग जब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा तब से ही इस चुनौती को अवसर में बदलने की बातें सोचने विचारने तथा बताने लगे थे और देशभर के कार्यकर्ताओं ने इसे अपनाया भी है ।

अपने अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कालखंड में परिषद ने सामान्य स्थितियों से भी ज्यादा रचनात्मक कार्यक्रम किये हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को प्रत्यक्ष करने में हजारों रुपये का बजट, स्थान, साधन सुविधायें लगती है लेकिन ऑनलाइन माध्यमों ने हमारी रचनात्मकता को बहुत ही सहज सुलभ बना दिया ताकि हम बिना साधन – सुविधा के बड़े से बड़ा कार्यक्रम श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ सहजतापूर्वक कर सकें। हालांकि यह भी सच है कि संगठन कार्य विस्तार में ऑनलाइन माध्यम विकल्प नही , सहयोगी हो सकते हैं।

2. तकनीक का सदुपयोग – वैसे तो भारतवर्ष में 1990 के दशक से ही उदारीकरण के दौर के बाद धीरे – धीरे नवीनतम तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है ! लेकिन 2010 के बाद गत दशकों में युवा वर्ग ने इसको बहुत ही तेज गति से अपनाया। आज दुनिया के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाईल मार्केट भारत में हैं लेकिन अधिकांश लोग मोबाईल सहित इस संवाद क्रांति के साधनों का उपयोग कॉल करने, फोटो खीचने, वीडियो देखने, संगीत सुनने में करता है। इस कोरोना कालखंड में हमें इसकी ओर अधिक उपयोगिता बताई है। “वर्क फ्रॉम होम” जैसा कन्सेप्ट हमारे लिए बिल्कुल नया है । ये एक क्रांति जैसा बदलाव है और इस समय इस क्रांति ने देश दुनिया के समान्य आदमी के जीवन में बदलाव किया है। देखिये जूम आदि एप्प के माध्यम से लगभग हर परिवार सामूहिक रूप से आपस में जुड़ा है। आम आदमी के जीवन में आये इस बदलाव से समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों ने इसको अपनाते हुए, अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव किये हैं। परिषद ने भी तकनीकी दुनिया की आधुनिकतम साधनों का उपयोग करते हुए अपनी कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव किये हैं। संगठनात्मक बैठकें, रचनात्मक कार्यक्रम, प्रतियोगिता सेवा कार्य , वेबिनार आदि यहां तक कि विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन आंदोलन भी परिषद ने किये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फोन सेवा के माध्यम से चलाया गये राष्ट्रीय राष्ट्रीय संपर्क अभियान ने तो संगठन की बैठक, प्रवास, संपर्क की कार्यपद्धति को कुछ हद तक चलाये रखने में सफल हुए हैं, जिसमें महीनों से घर में बैठे विद्यार्थियों ने परिषद के अपनेपन को निकटता से देखा है !

3. सेवा संस्कार का जागरण – अभी तक युवाओं के इस संगठन में रचनात्कता, आंदोलन वृति कार्यों की अधिकता रहती थी। पिछले कुछ समय से “स्टूडेंट फॉर सेवा” के माध्यम से लगातार सामाजिक अनुभूति के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रमों में सेवावृति बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है । 70 वर्ष से अधिक पुराने संगठन में देखे तो देशभर में सेवा कार्य बहुत ही कम चलते हैं लेकिन मार्च महीने मे जैसे ही लॉकडाउन लगा परिषद ने सबसे आगे रहते हुए देशभर में प्रांत, जिला, नगर स्तर पर सबसे पहले हेल्पलाईन जारी करते हुए सेवा कार्यों में जुटने का आह्वान किया। देशभर में विद्यार्थियों की घर वापसी, जहां हैं वहीं उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करना, देशभर में मजदूरों की घर वापसी, आवश्यकता जनित क्षेत्रों में दवा, लंगर भोजन, राशन वितरण आदि कार्यों में देश भर की इकाईयों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। बस्ती की पाठशाला अथवा परिषद की पाठशाला जैसा अभिनव प्रयोग इस कालखंड की ही देन हैं जब स्थानों - स्थान पर परिषद कार्यकर्ताओं ने शिक्षा से वंचित रहे बच्चों को उनकी ही बस्ती में जाकर पढ़ाना शुरू किया तो यह सेवा कार्य देश भर में एक आंदोलन बन गया।

कोविड 19 की रोकथाम हेतु ग्राम प्रहरी, जागरूकता आदि ग्राम संगठन आदि के प्रयोगों के साथ सरकार के साथ मिलकर स्थान – स्थान पर प्रत्यक्ष सेवा कार्यों में सहभाग किया। मुंबई के धारावी बस्ती में तो परिषद कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट पहनकर स्क्रीनिंग कार्य बड़ी

मात्रा में किया है। इस काल में परिषद कार्यकर्ता के स्वभाव में सेवा संस्कार का स्वाभाविक जागरण हुआ है।

4. आयाम गतिविधि कार्य विस्तार – गत कुछ वर्षों से विद्यार्थी परिषद में विविध आयामों, गतिविधियों, प्रकल्पों, कार्यों का सहभाग बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि यह एक समान्य सिद्धांत है कि जब संगठन, संस्था अथवा परिवार का विस्तार होता है। वहां कार्य विभाजन तथा नये – नये क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रयास करना होता ही है। परिषद का कार्य जब चलते – चलते 17 वर्ष हो गये थे तब 1966 में पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष कार्ययोजना 'अंतर राज्य छात्र जीवन दर्शन' का कार्य प्रारंभ किया था ! उसके बाद समय – समय पर आवश्यकता अनुसार 'जहां छात्र – वहां परिषद' का संकल्प लेकर 'दशों दिशाओं में जायें दल बादल से छा जायें' के लक्ष्य के साथ अनेकों प्रकल्प, गतिविधि, कार्यों तथा आयामों का कार्य शुरू हुआ जैसे WOSY, THINK INDIA, छात्रा कार्य,जनजाति कार्य, विश्वविद्यालय कार्य, SFD, SFS, राष्ट्रीय कला मंच, मेडिविजन, एग्रीविजन, जिज्ञासा, तकनीकी कार्य आदि शुरू किये गये।

आज परिषद की पहचान केवल समान्य डिग्री महाविद्यालयों में चलने वाले आंदोलनकारी संगठन अथवा छोटी – मोटी गतिविधियां करने वाले वैचारिक संगठन की नहीं है अपितु जहां छात्र है वहां भिन्न – भिन्न नामों से उनके रूचि के विषय के अनुसार कार्य करने वाले संगठन की है। पर्यावरण, सेवा और कला संस्कृति विषयों पर कार्य के आग्रह करके परिषद ने गत कुछ वर्षों से महाविद्यालय इकाई तक SFD, SFS, राष्ट्रीय कला मंच का दायित्व दिया है। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम, प्रांत स्तर पर प्रमुख कार्यकर्ता को दायित्व दिये हैं, इसी का परिणाम है कि कार्यकर्ताओं ने नीचे तक बड़ी मात्रा में गतिविधियों का आयोजन किया। कोरोना काल इन गतिविधियों के लिए भी एक अवसर बन कर आया जिसमें कार्यकर्ताओं ने देश भर में सेवा कार्य किये। सबसे पहले देश भर में हेल्पलाईन जारी करने वाला विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। हजारों विद्यार्थियों का सहयोग तथा अनेकों संबल प्रदान किया। घर वापस जाते मजदूरों को भोजन पानी भी पहुंचाया,आवश्यकता जनित क्षेत्रों में भोजनशाला, लंगर चलाये जहां जिस इकाई की जितनी सामर्थ्य रही। आवश्कता लगी सेवा कार्य किये। सरकार को विविध कार्यों के लिए स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी तो उसके लिए आगे आयें।

अब कार्यकर्ताओं का सेवा करना स्वभाव बन गया है। सेनिटाईजर, मास्क वितरण किये इसी प्रकार पर्यावरण गतिविधियां, सांस्कृतिक प्रतियोगितायें आदि का आयोजन देश भर में विविध स्वरूपों में हुआ। घर बैठे कार्यकर्ताओं ने नये – नये आईडिया को साकार रूप दिया। नये कार्यक्रम शुरू किये।

गत कुछ वर्षों में परिषद की कार्यप्रणाली, कार्यकर्ता के मन का विकास अनेक स्वरूपों में परिषद में देखने को मिल रहा है। दो – तीन वर्षों में बदलने वाला कार्यकर्ता अब स्थायीत्व का गुण एवं स्वरूप पर विचार कर रहा है। स्थायी कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, स्थायी कार्यालय भवन सभी कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं के समूह और समूहों के लिए कार्य देना अब परिषद का स्वभाव बन रहा है। शिक्षा के साथ – साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव हमारे कार्यों में दिख रहा है। यही बदलाव, समय के साथ चलने की पहचान है। ■

(लेखक अभाविप उत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं।)

प्रिय मित्रों !

शिक्षा - क्षेत्र की प्रतिनिधि - पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' दिसम्बर 2020 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों व खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव व विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई - मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti

बेगूसरायः अभाविप कार्यकर्ताओं ने लगाये 'नेकी की दीवार'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार के कार्यकर्ताओं के पहल की चारो तरफ प्रशंसा हो रही है। दरअसल अभाविप कार्यकर्ताओं ने बेगूसराय के बिहट में जरूरतमंदो के लिए 'नेकी की दीवार लगाया' है, जब से यह दीवार लगाया गया है तब से यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 'नेकी की दीवार' के बारे में जानकारी देते हुए अभाविप कार्यकर्ता बताते हैं कि अगर आपके घर में पुराने पहनने, ओढ़ने, बिछाने के साफ कपड़े, किताबें, खिलौना,बर्तन,क्रॉकरी, फर्नीचर आदि जो भी है,जिसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं और वह नगर के जरूरतमंदों के काम आ जाए, तो आप उक्त सामान को 'नेकी की दीवार' को दे दीजिए। यहां से जरूरतमंद आकर खुद इन्हें ले जाएंगे। कपड़े टांगने के लिए यहां खूंटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा बर्तन आदि अन्य सामान रखने के लिए नीचे जगह बनाई गई है। यहां जरूरतमंद आकर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज ले सकता है। नेकी की यह दीवार उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।अपने स्वाभिमान के कारण किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जरूरतमंद लोग यहां आकर अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें ले सकते हैं।

नाम से ही जाहिर है कि यह नेकी की दीवार है,लेकिन ये दीवार बांटने के लिए नहीं बल्कि समाज को जोडने के लिए खड़ी है।अभाविप की यह पहल सराहनीय है।आपकी द्वारा दी गई ये चीजें किसी गरीब की जरूरतों को पूरा कर उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। बेगूसराय के बीहट इकाई में कार्यकर्ताओं ने बनाई नेकी की दीवार,एक तरफ लिखा "जो आपके पास अधिक है यहां छोड़ जाएं" ...... तो दूसरी तरफ लिखा "जो आपकी जरूरत है यहाँ से ले जाएं"। स्थानीय लोग बताते हैं कि अभाविप के कार्यकर्ताओं की यह पहल सराहनीय है, हमारे यहां कई ऐसे वस्तुएं जो काम के नहीं हैं लेकिन यह किसी के काम में आ सकता है इसे हमने नेकी की दीवार से जाना। जिन्हें कपड़े देने होते हैं वे यहां आकर बिना कुछ कहे दीवार पर लगी कील में टांगकर चले जाते हैं। पहले हमलोग को अपने पुराने या जरूरत से अधिक रखे कपड़े को किसी को देने में संकोच होती थी लेकिन अब हम निःसंकोच यहां पर रख जाते हैं जिसे जरूरतमंद अपने उपयोग में ला सकते हैं। वहीं एक वृद्ध रिक्शाचालक जिनका यहां नाम लिखना उचित नहीं होगा, से नेकी की दीवार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बाबू जबसे लॉकडाउन हुआ है कमाई – धमाई बंद हो गई है। यात्रियों की संख्या भी घट गई है। गर्मी तो जैसे – तैसे एक दो कपड़े में निकल जाते थे लेकिन अब सर्दी आ चुकी है किसी से कुछ मांगने में भी खराब लगता है। इसी बीच हमें किसी ने बताया कि यहां पर नेकी की दीवार लगाई हैं जहां पर अपने जरूरत के हिसाब से कपड़े, बर्तन इत्यादि ले सकते हैं, उसकी बातों को सुनकर यहां पर आया तो देखा उसने तो सच ही कहा था। हमने भी अपने जरूरत के मुताबिक स्वेटर इत्यादि को लिया, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। ■

रोशनी एक्ट उर्फ़ जमीन जिहाद और गुपकार गैंग की फुफकार

| प्रो. रसाल सिंह |

9 अक्टूबर, 2020 का दिन जम्मू-कश्मीर की तवारीख के चुनिन्दा महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस ऐतिहासिक दिन इकजुट जम्मू संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में दायर किये गए दो वादों (PIL-41/2014 और CMP-48/2014) पर अपना निर्णय देकर उनके पक्ष की पुष्टि की। पहले वाद में उन्होंने रोशनी एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की थी। सन् 2001 में फारुख अब्दुल्ला की सरकार द्वारा पारित किये गए 'द जम्मू-कश्मीर स्टेट लैंड्स (वेस्टिंग ऑफ़ ऑनरशिप टू द ओक्युपेंट्स) एक्ट-2001' के तहत राज्य सरकार ने मामूली कीमतें तय करते हुए सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने वाले लोगों को ही उस भूमि का क़ानूनी कब्ज़ा देने का प्रावधान कर दिया। सबसे पहले सन् 1990 तक के कब्जों को वैधता देने की बात हुई फिर बाद की मुफ़्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद की सरकारों ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तिथि को आगे बढ़ाते हुए 2003 और 2007 तक के अवैध कब्जों को भी वैधता प्रदान कर दी। इस कानून को रोशनी एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इससे अर्जित धन से राज्य में बिजली परियोजनाएं लगाकर विद्युतीकरण करते हुए राज्य में रोशनी फैलानी थी। लेकिन इसका ठीक उलट काम हुआ। न सिर्फ सरकारी जमीन की बंदरबांट और संगठित लूट-खसोट हुई,बल्कि जम्मू संभाग के जनसांख्यकीय परिवर्तन की सुनियोजित साजिश भी हुई। इस एक्ट के लाभार्थियों की सूची देखने से साफ़ पता चलता है कि यह जम्मू संभाग के 'इस्लामीकरण' का सरकारी षड्यंत्र था। उदाहरणस्वरूप जम्मू के उपायुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के अनुसार तवी नदी के कछार में अतिक्रमण करने वाले 668 लोगों में से 667 मुस्लिम

समुदाय से हैं। तमाम रोहिंग्या और बंग्लादेशी घुसपैठिये भी इसके लाभार्थी रहे हैं। जम्मू शहर की सीमावर्ती वनभूमि पर बसायी गयी भटिंडी नामक कॉलोनी (जिसे स्थानीय लोग 'मिनी पाकिस्तान' कहते हैं) एक और उदाहरण है। हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बंग्लादेशी घुसपैठिये भी इसके 'लाभार्थी' रहे हैं। सुन्जवां और सिद्धड़ा भी अतिक्रमण के बड़े ठिकाने हैं।

यह धर्म-विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाकर, विशेष रूप से जम्मू संभाग में उनके वोट बनवाकर और बढ़वाकर लोकतंत्र के अपहरण और अपनी सत्ता के स्थायीकरण की बड़ी सुनियोजित और संगठित कोशिश थी। रोशनी एक्ट वास्तव में भ्रष्टाचार और जेहादी एजेंडे के कॉकटेल की बेमिसाल नज़ीर है। अपने दूसरे वाद में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने 25 हजार करोड़ से ज्यादा मूल्य की इस साढ़े तीन लाख कैनाल भूमि की लूट-खसोट की जाँच ACB की जगह सीबीआई से कराने की मांग की, ताकि इस गुनाह में शामिल रसूखदार नेता और नौकरशाह जाँच को प्रभावित न कर सकें। ज्ञातव्य है कि

इस लूट-खसोट में न सिर्फ मंत्री, सांसद, विधायक आदि राजनेता बल्कि पुलिस-प्रशासन के आला अफसर भी शामिल रहे हैं। सर्वप्रथम सन् 2011 में प्रोफ़ेसर एस के भल्ला इस मामले को एक जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय में लेकर गए । उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस भूमि घोटाले की वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी बदनीयती पर प्रश्नचिह्न लगाये गये। उसके बाद श्री अंकुर शर्मा ने इस मामले को अंतिम परिणति तक पहुंचाते हुए देश की आँख खोलने वाले इस भूमि घोटाले का पर्दाफाश करने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस भ्रष्टाचार में नेताओं, नौकरशाहों और भू-माफिया की आपसी सांठ-गांठ और धर्म-विशेष के लोगों को सुनियोजित लाभ पहुँचाने के कारण ही इसे 'जमीन जेहाद' भी कहा जा सकता है। यह घोटाला 'रक्षकों के भक्षक' बन जाने की लोमहर्षक कहानी है। संवैधानिक शपथ और राजधर्म की खुली अवहेलना और धार्मिक भेदभाव की दास्तान भी इस घोटाले की अन्तर्निहित पटकथा है।

रोशनी एक्ट की आड़ में सरकारी भूमि की लूट का आलम यह था कि नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियों के प्रदेश कार्यालय इसी एक्ट की आड़ में हथियायी गयी भूमि पर बने हैं। कांग्रेस-पी डी पी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने सैकड़ों करोड़ की सरकारी भूमि अपने चहेतों को कौड़ियों के भाव आवंटित कर दी। गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गुलाम रसूल कार जिस ख़िदमत ट्रस्ट के न्यासी रहे हैं, वह भी बड़े अतिक्रमणकारियों की सूची में शामिल है। फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनकी बुआ सुरैय्या अब्दुल्ला मट्टू और खालिदा अब्दुल्ला शाह, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह के साहिबजादे , भांजे और अन्य कई परिजन, पी डी पी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हसीब द्राबू और काजी मोहम्मद अफ़ज़ल के बेटे टीपू सुल्तान, कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री के के अमला, अब्दुल मजीद वानी और ताज मोहिउद्दीन, नैशनल कॉन्फ्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद अहमद किचलू, तनवीर किचलू, सैय्यद आखून,जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव मोहम्मद शफी पंडित, पूर्व एडवोकेट जनरल असलम गोनी, जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन एम वाई खान, पूर्व न्यायाधीश अली मोहम्मद के साहिबजादे अशफाक अहमद मीर, पूर्व पुलिस अधिकारी नासिर अली, खालिद दुर्रानी और मिर्ज़ा रशीद, पूर्व वन अधिकारी कमर अली और सुल्तान अली, उद्योगपति मुश्ताक छाया, मोहम्मद सलीम बख़्शी और मोहम्मद हुसैन जान, ओवेस अहमद, जमात अली जैसे 'बड़ी पहुंच वाले' लोग भी इसके लाभार्थी हैं। ये सूची जम्मू और कश्मीर संभाग के मंडलायुक्तों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी की जा रही हैं। सी बी आई जाँच आगे बढ़ने पर उसके जाल में और भी अनेक बड़ी मछलियां फंसेगी।

धर्म विशेष (हिन्दू धर्म) और क्षेत्र विशेष (जम्मू संभाग) के लोगों के साथ भेदभाव और उपेक्षा और सरकारी संसाधनों की लूट-खसोट और बंदरबांट यहाँ की सरकारों का स्वभाव रहा है। इसलिए इस जाँच से गुपकार गैंग के पेट में दर्द होना अस्वाभाविक नहीं है। गुपकार गैंग में नैशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पी डी पी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ए मीर जैसे कई नेता (जिन्हें कि गुलाम नबी आज़ाद और पी चिदम्बरम जैसे केन्द्रीय कांग्रेसी नेताओं की शह मिली हुई है) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद युसूफ तारिगामी आदि शामिल हैं। गुपकार गैंग स्वार्थप्रेरित और बेमेल गठजोड़ है। यह 5 अगस्त 2019, 31 अक्टूबर 2019 और 9 अक्टूबर 2020 जैसे कुछ दूरगामी निर्णयों से खिसियायी बिल्लियों की मिलीभगत से बना एक ऐसा गिरोह है जोकि मिलकर खम्भा नोंचने की कोशिश कर रहा है। यह गिरोहबंदी ख़ुद के अप्रासंगिक होते जाने की आशंका की भी उपज है। जम्मू-कश्मीर की जनता इस अपवित्र और अवसरवादी गठजोड़ के वास्तविक मंसूबों से अनभिज्ञ नहीं है। जिस गुपकार गैंग के सरगना आज केंद्र सरकार की विभिन्न विकासवादी और राष्ट्रीय एकीकरण वाली नीतियों से जम्मू-कश्मीर की 'डेमोग्राफी' के बदलने का बेसुरा राग अलाप रहे हैं, वे स्वयं जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को बदलने के गुनाह में संलिप्त रहे हैं। सन् 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़े और सन् 2000 से पहले और बाद की मतदाता सूची इस तथ्य की तस्दीक करते हैं।

9 अक्टूबर, 2020 को दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में जम्मू-कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय ने न सिर्फ रोशनी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बल्कि देश के इस सबसे बड़े भूमि घोटाले और जम्मू संभाग के इस्लामीकरण की जेहादी साजिश की जाँच सीबीआई को सौंप दी। अब इस घोटाले की जाँच उच्च न्यायालय की निगरानी में हो रही है और सीबीआई को भी हर 8 सप्ताह बाद नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उच्च न्यायालय में जमा करनी पड़ती है। जैसे-जैसे यह जांच रफ़्तार पकड़ रही है, नए-नए राज़फाश हो रहे हैं। जम्मू-कश्मीर को निजी जागीर समझकर अदल-बदलकर शासन करने वाले 'शाही ख़ानदानों' की बदहवाशी,बेचैनी और बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जो सियासी दुश्मन होने का नाटक रचते हुए सत्तर सालों से जम्मू-कश्मीर के लोगों को बरगलाते हुए लूट और झूठ की राजनीति में आकंठ डूबे हुए थे, वे आज गुपकार घोषणा-पत्र के नाम पर नापाक गठजोड़ बना रहे हैं और जम्मू-कश्मीर की भोली-भाली जनता को एकबार फिर बेवकूफ बनाने की साजिश रचने में मशगूल हो गए हैं। आज 'रोशनी एक्ट' के अंधेरों से जम्मू-कश्मीर का आम नागरिक परिचित है। तमाम राजनेताओं और नौकरशाहों ने इस एक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि को हड़प लिया था। अब उस जमीन का हिसाब-किताब किया जा रहा है और उसे इनके कब्जे से मुक्त कराकर आम जनता की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप उपयोग करने की सम्भावना बन रही है। जम्मू-कश्मीर में हाल तक जारी अंधेरगर्दी और अराजकता पर अंकुश लगने से घबराये हुए नैशनल कॉन्फ्रेस और पी डी पी जैसे चिर-प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल भी अब एक मंच पर आ रहे हैं। वस्तुतः, गुपकार गैंग जम्मू-कश्मीर के लुटेरों और मतलबपरस्तों का मौकापरस्त गठजोड़ मात्र है।

अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए फारुख अब्दुल्ला द्वारा चीन से सहायता लेने की बात करना और महबूबा मुफ़्ती द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली तक तिरंगा न उठाने की बात कहना इस गठजोड़ और इसके आकाओं की असलियत का खुलासा करते हैं। चीन और शेख अब्दुल्ला परिवार दोनों ही पंडित जवाहर लाल नेहरू की आँखों के तारे थे। आज सारा देश इन दोनों की कारनामे और असलियत देख रहा है। उल्लेखनीय है कि रोशनी एक्ट तो गुपकार गैंग की कारस्तानियों की बानगी भर है। अभी ऐसे अनेक कच्चे चिट्ठे खुलने बाकी हैं। रोशनी एक्ट वाली जाँच में तो मात्र साढ़े तीन लाख कैनाल भूमि की लूट का ही हिसाब-किताब हो रहा है। जाँच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि साढ़े तीन लाख कैनाल भूमि 'लुटाने' से कितनी कमाई हुई, उससे कितने पॉवर प्रोजेक्ट लगे और कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ। इसके नीति-नियंताओं की नीयत के मद्देनज़र सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका परिणाम ढाक के तीन पात से ज्यादा कुछ न हुआ होगा। इसके अलावा सन् 2014 के आंकड़ों के अनुसार साढ़े सत्रह लाख कैनाल वन भूमि, नदी भूमि और अन्य भूमि पर धर्म विशेष के लोगों ने और रसूखदार नेता और नौकरशाहों ने अतिक्रमण कर रखा है। उस सबका हिसाब होना बाकी है। एक ऐसा ही कारनामा तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती का 14 फरवरी, 2018 का वह फरमान है जिसके तहत जम्मू संभाग में सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने वाले किसी भी घुमंतू जनजाति के (मुस्लिम) व्यक्ति पर डी सी या एस पी कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि न्यायालय की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई आदेश आता है, तो भी पुलिस ऐसे मामलों में प्रशासन की सहायता नहीं करेगी। गौहत्या और गौवंश की तस्करी करने वालों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये सारी की सारी कारगुजारियां सांप्रदायिक तुष्टिकरण और मुस्लिम ध्रुवीकरण का नायाब उदाहरण हैं। इनका विरोध करना साम्प्रदायिकता है और आंख मूंदकर इनका समर्थन करना सेकुलर होना है। भारत में सेकुलरिज्म की दुनिया से अलग और अजब परिभाषा चलती है।

पिछला एक साल जम्मू-कश्मीर के लिए निर्णायक रहा है। अब यहां जमीनी बदलाव की आधारभूमि तैयार हो चुकी है। कई पुराने कानूनों को या तो निरस्त किया गया है या फिर उनमें आवश्यक संशोधन किये गए हैं। ऐसा करके न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के शेष भारत के साथ एकीकरण की सभी बाधाओं और अड़चनों को समाप्त किया गया है बल्कि समृद्धि, प्रगति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर की नयी अधिवास नीति, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति और भाषा नीति में बदलाव करते हुए हर तरह की दूरी और अलगाव को खत्म किया जा रहा है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिला विकास परिषद्

के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी जम्मू-कश्मीर की औद्योगिक नीति भी घोषित होने वाली है। जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने 'चलो गांव की ओर' और 'माइ सिटी माइ प्राइड' जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करके शासन-प्रशासन को जनता से जोड़ने और उसे संवेदनशील बनाने की पहल की है। ये कार्यक्रम विकास योजनाओं में जनभागीदारी पर बल देने वाले हैं। सभी हितधारकों ख़ासकर आम नागरिकों में भरोसा पैदा करके और उन्हें साथ जोड़कर ही सरकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन संभव है। जम्मू-कश्मीर भू-स्वामित्व कानून में बदलाव के बाद उनके द्वारा आयोजित 'निवेशक सम्मेलन' का विशेष महत्व है। इस सम्मेलन में देश के 30 शीर्षस्थ उद्योगपतियों ने भागीदारी करते हुए जम्मू-कश्मीर में भारी आर्थिक निवेश के प्रति आश्वस्त किया है । यह निवेशक सम्मलेन नयी संभावनाओं का सूत्रपात करने वाला है।

नए भू-स्वामित्व कानून के सम्बन्ध में गुपकार गैंग यहाँ के मूल निवासियों को भड़काने की साजिश कर रहा है और उसके आका "जम्मू-कश्मीर ऑन सेल" जैसे भ्रामक बयान दे रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की भांति सुरक्षात्मक प्रावधान किये गए हैं। कृषि भूमि को जम्मू-कश्मीर के कृषकों को ही बेचा जा सकता है। सरकार ही औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि चिह्नित करते हुए किसानों को बाजार मूल्य देकर उसका अधिग्रहण करेगी और उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित करेगी। इसलिए 'बाहरी' लोगों द्वारा जम्मू-कश्मीर की भूमि हथियाने की आशंकाएं निर्मूल हैं। यह संशोधित कानून नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना द्वारा जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मुहैय्या कराएगा। अन्य नौकरीपेशा और कामकाजी भारतीयों के यहाँ बसने से भी अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता पैदा होगी। इस नयी नीति के लागू हो जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पूँजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जिसप्रकार सन 1991 के बजट के बाद भारतीय अर्थ-व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे, ठीक उसीप्रकार के परिवर्तन के मुहाने पर अभी जम्मू-कश्मीर है। पूँजी-निवेश और आर्थिक-पुनर्नियोजन के लिए उसके द्वार खुल चुके हैं। यह सचमुच एक ऐतिहासिक परिघटना है। पर्यटन, सीमेंट, बिजली, औषधिक सम्पदा, ऊनी वस्त्र, चावल, केसर, फल, मेवा, शहद और दुग्ध-उत्पाद आदि से सम्बंधित यहाँ के उद्योग-धंधे और व्यापार आवश्यक पूँजी-निवेश और नयी श्रम-शक्ति, कौशल और प्रतिभा से कई गुना विकसित होने वाले हैं। अगर ये उद्योग-धंधे और व्यापार अपनी पूर्ण-क्षमतानुसार विकसित होते हैं तो इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलेंगे। एकबार फिर उनके हाथ में पत्थर और बंदूक की जगह कलम-किताब और इलेक्ट्रॉनिक गजट होंगे।

जम्मू-कश्मीर ज्ञान-विज्ञान और दर्शन की उर्वरा-भूमि है। यहाँ की जीवन-शैली और चिंतन प्राचीन काल से ही उन्नत और प्रगत रहा है। बीच में गुपकार गैंग जैसे तत्वों द्वारा भोले-भाले लोगों को बरगलाने से कुछ अशांति, अवरोध और अंतराल पैदा हो गया था। अब पठन-पाठन और चिंतन की अड़चनों और अशांति की क्रमिक समाप्ति हो रही है। इसप्रकार एक विशेष अर्थ में यह जम्मू-कश्मीर की समृद्ध ज्ञान-परम्परा के नवजागरण की बेला भी है। यहाँ वैष्णो देवी और अमरनाथ धाम जैसे अनेक सर्वमान्य तीर्थस्थल हैं। यहाँ का वातावरण प्रदुषण-मुक्त है और श्रेष्ठतम शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य के अनुकूल है। इसलिए यहाँ प्राकृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य पर्यटन के विकास की अपरिमित संभावनाएं हैं। अब इन संभावनाओं का सुनियोजित विकास और सतत दोहन करने की आवश्यकता है। जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को देश की मुख्यधारा में शामिल करके और विकास-योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके ही पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को मात दी जा सकती है। शांति,सौहार्द, सद्भाव, समरसता और सहयोग किसी भी सभ्यता के पूर्णविकास की आधारभूमि हैं। कश्मीर की ज्ञान-समृद्ध सभ्यता अब प्रगति और परिवर्तन की राह पकड़ रही है। अपनी कारस्तानियों के उजागर होने से और अपनी विश्वसनीयता में आ रही लगातार गिरावट से गुपकार गैंग तिलमिला रहा है। इसलिए वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए हर हथकंडा आजमा रहा है और लोगों को बरगलाने की हरसंभव कोशिश कर रहा है। ■

(लेखक जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता हैं एवं ये उनके निजी विचार हैं।)

काशी : अभाविप ने अंगवस्त्र देकर कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह किये बगैर पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एंबुलेंसकर्मी समेत मानवता की सेवा में लगे सभी कोरोना योद्धाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। अभाविप काशी प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री विजय प्रताप ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड – 19 के डर से अपने घरों में थे उस समय डॉक्टर, पुलिसकर्मी, खाद्य आपुर्त्तिकर्ता, स्वच्छताकर्मी, एबुंलेसकर्मी जैसे कोरोना योद्धाओं ने अपने जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा की। दिन – रात बिना थके, बिना रूके लगातार लोगों को कोरोना के प्रति न केवल जागरूक किया अपितु उनकी जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। हमारे समाज में जितने महत्वपूर्ण पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स और स्वच्छताकर्मी हैं उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एबुंलेंशचालक भी हैं, कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान इन चालको की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह लोग बिना किसी संकोच के लगातार दिन – रात सेवा करते हैं।

वहीं प्रदेश सह मंत्री शुभम कुमार सेठ ने कहा कि अभाविप सेवा ही संकल्पना के मंत्र को आत्मसात करने वाला छात्र संगठन हैं। यही कारण है कि कोरोना संकट के दौरान भी अभाविप कार्यकर्ता लोगों की सेवा में डटे रहे, जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने का काम हो या प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान भेजने की व्यवस्था करना हो, हर मोर्चा पर परिषद कार्यकर्ता डटे रहे। हमारे समाज के डॉक्टर, स्वच्छताकर्मी, पुलिसकर्मी भी अपनी चिंता किये बगैर लगातार नागरिकों की सेवा में लगे रहे। ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर अभाविप के कार्यकर्ता गौरवान्वित हो रहे है। विद्यार्थी परिषद हमेशा ऐसे योद्धाओं की मदद एवं सहयोग करता रहेगा। इस दौरान परिषद कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर भी उन्हें देने का काम किया। ■

ABVP's 66th National Conference's poster released at the hands of National Joint Organising Secretary G. Laxman

ABVP's 66th National Conference is going to be held between 25th & 26th December 2020 at Dr.HedgewarSmrutiMandir, Reshimbagh, Nagpur. It is a privilege to conduct the conference at Nagpur after almost 24 long years. Representatives of ABVP from all the states and union territories of India would be attending the conference. The conference which otherwise marks presence of thousands of karyakartas would this year be held in a blended way with few representatives attending it in person while thousands of karyakartas across the country joining virtually at 4000 different locations. The two day conference would witness discussions on various educational and social issues. Also, a few resolutions relating to the same would also be proposed and passed. The annual national conference would guide karyakartas for the year long work also, catalyse the expansion of the organisation.

The poster for the conference was released at the hands of National Joint Organising Secretary G. Laxman at Nagpur today while guiding the student activists, he advocated and insisted working for organizing the event while taking safety measures considering the pandemic. He further said that the conference should be held by complying with all the pandemic norms.

Zonal Girls' Head PritiNegi, Nagpur City President Prof. Shruti Joshi, Nagpur City Secretary Karan Khandale and ABVP karykartas were present during the release. ■

देश के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान: कटारिया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी लक्ष्मीबाई जयंती को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाया। स्त्री शक्ति दिवस के मौके पर विद्यार्थी परिषद ने देश भर में अनेक कार्यक्रम, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन किया। अभाविप मेरठ प्रांत के प्रांत छात्रा सम्मेलन में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनु शर्मा कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।

रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपने जीवन में बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे कम उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया फिर मात्र 21 वर्ष की उम्र में उनके पति और पुत्र का देहांत हो गया फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी ना ही अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और सारी परेशानियों को हराते हुए अपनी सेना और प्रजा का नेतृत्व किया ।

कोरोना काल में भी हमारी देश की महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए समाज के लिए काम किया अभी हाल ही में महाराष्ट्र में विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर कर लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक किया तथा लाखों छात्र छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए शपथ ली ।मिशन साहसी के माध्यम से परिषद ने लगभग नौ लाख छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए।विद्यार्थी परिषद केवल समस्याओं को उजागर करने वाला संगठन नहीं बल्कि समस्याओं को समाधान तक ले जाने वाला संगठन है ।

अभाविप के द्वारा लक्ष्मी बाई की 192 वीं जयंती पर ग्वालियर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें 23 महिलायें घोड़ों पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुई ताकि समाज में प्रतीकात्मक संदेश जाय। यह 23 महिलाएं किसी भी उम्र की हो सकती हैं जिससे यह पता चले कि लक्ष्मी बाई हर वर्ग की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा और आदर्श का प्रतीक हैं।शोभा यात्रा शहर के मुख्य स्थानों से गुजरती हुई, रानी लक्ष्मी बाई जी के पवित्र समाधि स्थल पर जाकर सभा में परिवर्तित हो गई। सभा को राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार अधिका अक्षिक ने संबोधित किया। इसी कड़ी में पथरिया(छत्तीसगढ़) में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

बरेली(ब्रज) में प्रांत छात्रा सम्मेलन को दो सत्रों में आयोजित किया गया। पहला सत्र वर्चुअल माध्यम से था दूसरा प्रत्यक्ष उपस्थिति (फीजिकल)। सम्मेलन का प्रास्ताविक भाषण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. भूपेन्द्र ने दिया। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि दंगल गर्ल बबिता फोगाट ने कहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी शक्ति की पहचान कर लड़ना चाहिए। वहीं अभाविप की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाते हुए स्त्री सेना का निर्माण किया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा ने कहा कि आप सभी बहनों को भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बनकर समाज में हो रहे अन्याय का डटकर सामना करना होगा।

द्वितीय सत्र में अभाविप ब्रज के प्रांत संगठन मंत्री जयकरन ने कहा महारानी लक्ष्मीबाई हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज हैं। प्रांत स्तरीय छात्रा सम्मेलन में वर्चुअल रूप से1072 छात्राओं ने प्रतिभाग किया तथा 178 छात्रा प्रत्यक्ष उपस्थित थीं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से 22 हजार से अधिक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। ■

पुणे: आईआईएसईआर प्रशासन के खिलाफ अभाविप ने किया प्रदर्शन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मणिपुर के रहने वाले शोध छात्र बोरिश की मृत्यु पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Science Education and Research – IISER), पुणे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। अभाविप ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि बोरिश की मृत्यु के जिम्मेवार लापरवाह प्रशासनिक एवं चिकत्सीय अधिकारियों पर अविलंब कार्रवाई हो एवं मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाय। अभाविप का कहना है आईआईएसईआर प्रशासन की लापरवाही के कारण देश ने एक होनहार वैज्ञानिक को खो दिया है।

अभाविप, पुणे के महानगर मंत्री अनिल ठोंबरे ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2020 में कोविड -19 महामारी के कारण देश भर में तत्काल लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के कारण फंसे छात्रों में से कई पूर्वोत्तर भारत के (मणिपुर)आईआईएसईआर (IISER) में पढ़ रहे पीएचडी (PhD) के छात्र थे। इस कोरोना संकट के दौरान, उनलोगों ने कोरोना वायरस पर आईआईएसईआर के एक अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करके सामाजिक कार्यों में योगदान देने का फैसला लिया, लेकिन बोरिश नामक एक छात्र को दुर्भाग्य से समाज के लिए अपनी निः स्वार्थ सेवा करने के लिए बहुत मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। बोरिश 24 अक्टूबर को बीमार पड़ गया, दो दिन बाद 26 अक्टूबर को उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सा विभाग ने 28 अक्टूबर को उसकी कोविड -19 रिपोर्ट नकारात्मक आने से पहले ही उसे कोविड -19 से ग्रसित मरीज़ो के साथ इलाज करना शुरू कर दिया था, भले ही उस समय उसकी 21,000 कोशिकाएं थीं।

अनिल बोंबरे ने आईआईएसआर को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि संस्थान के चिकित्सा विभाग ने बोरिश जैसे समर्पित छात्र के अंतर्निहित बीमारी की परवाह किए बिना कोविड -19 के साथ उसका इलाज करना जारी रखा और आईआईएसईआर, पुणे की लापरवाही के कारण बोरिस की जान चली गई। इस लापरवाही के कारण, भारत ने अपने भविष्य का एक शानदार वैज्ञानिक खो दिया है और उन्होंने कहा कि बोरिश की मौत का संपूर्ण आईआईएसईआरप्रशासन ज़िम्मेदार है। जब सरकार आईआईएसईआर पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, तब भी छात्रों के स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में हमलोंगो नेराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर

पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं आईआईएसईआर, पुणे के प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है।

अभाविप के कार्यकर्ता #JusticeforBorishके तख्ती लेकर आईआईएसईआर, पुणे के सामने धरने पर बैठ गए और संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभाविप के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब तक बोरिश के मृत्यु के जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी मांग है कि संस्थान, लापरवाह प्रशासनीक एवं चिकित्सीय अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करे एवं बोरिश के परिवार वाले को उचित मुआवजा दे। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में अभाविप का आंदोलन और अधिक उग्र होगा और हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन में अभाविप पुणे महानगर के प्रमुख पदाधिकारी समेंत सैंकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए पुणे से गोंविद देशपांडे की रिपोर्ट)

Farmers' strike has notable lessons

| K.N. Pandita |

The recent strike by sections of Punjab-Haryana farmers may not arguably pass for a nationwide strike. Nevertheless, some political opposition parties and those with vested interest tried to expand the strike to other states as well. Thus behind the cover of farmers' protest, these political parties have been trying to challenge the sovereignty of the Parliament. It is politics of disruption and not of nation-building. However, notwithstanding its geophysical aspects, we should not shy away from making a dispassionate analysis of the upsurge because for more than one reason it is a notable event in the contemporary political history of India.

To bring pressure on the government thousands of farmers from the states of Punjab and Haryana blocked the main entry and exit routes to the capital city of Delhi and paralyzed the entire transport system. They refused to assemble at a specific open space in the town where the Home Ministry was prepared to provide them with logistic facilities so that normal traffic was not disrupted. Most of the farmers came on their tractors, trucks, wagons and cars purposefully to strengthen the siege of the highways. They carried with them eatables, furnishing and bedding etc. and some unidentified organizations provided them with freshly cooked food. The protesting crowds refused food and tea arranged by the government as a gesture of courtesy. This indicates that the bundh was meticulously planned and it is not a fitful reaction to the new laws.

Politically oriented anti-government and anti-national slogans were raised frequently. It showed that the protestors designed to score a political victory and not get their grievances redressed. The dharna reminded one of Shaheen Bagh episode. Political undertones of the dharna were conspicuously eloquent.

The activists of opposition parties grabbed the opportunity and almost hijacked the protest rally. In the garb of protesting farmers, they began delivering threats to the government from the farmers' platform. The Home Minister addressed the media channels that the welfare and safeguarding the interests of the farmers was the foremost priority with the government and the new laws passed by the parliament were strictly in their interest. He added that in the past dissenting political parties had demanded passing of these laws. The government took

the initiative and brought to completion a task which his predecessors had once mulled over. He assured that the government was prepared to talk to the representatives of the farmers on the issue. This assurance was given by the Home Minister publicly.

Several rounds of talks were held but with no concrete result. As the interaction proceeded, the disgruntled farmers continued their hostility, raising unbecoming slogans. The norms of addressing the government or the Prime Minister were thrown to the wind. One got the impression that the farmers had not come really to get their problems solved but wanted to pour out disgust against the government. All opposition parties came out in support of the protesting farmers.

In such a situation, any responsible opposition would play a mature role to de-escalate tension and normalize the atmosphere. It would lend its helping hand in bringing about an amicable settlement of the issues involved. But unfortunately, the opposition parties, whether on national or on a regional level, began acting like hungry wolves to seek their pound of flesh. Their all efforts converged on bringing about the downfall of the government and not redressing the grievances of the farmers if any.

The lesson one can figure out from this situation is that despite seventy-three years of democracy, our nationalist sentiment is frail and vulnerable to the claptrap of political rant. One more lesson that we should learn from this event is that only a very thin line separates self-aggrandizement from nationalist predilection. Party workers can go to any length in removing the elected government instead of removing the hardships facing people or those in the way of a sincere elected government in alleviating the grievances of the people.

When dialogue between the government and the farmers did not make headway, the Congress President, playing the politics of vendetta, gave a call for Bharat bundh. Don't forget that the culture of Bharat bundh is closely associated with the Congress, tracing its history to the days of the freedom movement. But curiously, shorn of its traditional popularity and bereft of its spatial dimension, the present Congress remains unfazed by a call it gave with no takers.

Who are the ring leaders of the protest dramatics and what is their motivation, is a very pertinent question? Knowledgeable sources are if the opinion that a variety of stakeholders have jumped on the bandwagon and the entire show is almost a replication of Shaheen Bagh episode. Most of the ring leaders from Punjab are well-known affluent Leftists with clout in the Punjab peasantry. Besides them, there are Khalistanis and Congress loyalists as well. Remember that the slogan of Khalistan Zindabad was also raised by a section of the protesting crowds during Delhi bundh. The Congress came out in open to oppose the government proving that they are pursuing political vendetta and not the debilities in new agrarian rules.

The Congress, after its defeat in two successive parliamentary elections, has abandoned the standard role of genuine opposition in and outside the parliament and taken a hostile and antagonistic role bordering on a personal vendetta. Disrupting the sessions of the Parliament, opposing every bill brought by the ruling party irrespective of its merits and demerits, contradicting all facts and figures provided officially by the government to the parliament, undermining the mega developmental projects envisaged by the government and criticizing the government for its domestic as well as foreign policy without understanding the nuances, that is the attitude adopted by the party now at the backbenches in the parliament.

Not only that. The Congress loyalists and beneficiaries of expatriate Indians, especially in the UK and USA, have embarked on a massive anti-India mission and are whipping up class, sectarian and communal passions among the broad sections of Indian society by manipulating media and other sources of public information. The Khalistanis are working hand in glove with the Pakistanis in foreign capitals in encouraging anti-India

protest rallies, whipping up sectarian passions by publicizing fake and false stories or visuals to malign the Indian government. A close study of their activities will reveal that there is only the personal vendetta against prime minister and no word about the so-called stifling of the farmers.

It is to be noted that under the new law, farmers have the freedom of selling their products to any buyer, private or public, without any hindrance. The need to introduce the new law arose because some middlemen were not only amassing mountains of wealth by way of commission from the government and favours from the farmers but were reported to be misusing the enormous amounts in various activities that were not at all desirable as far as the national security is concerned. The middlemen have created a mafia that would want to prevent the farmers from selling the crops to a buyer ready to pay a higher price to the benefit of the farmers. It is this mafia which has given space to terrorists, anti-national elements, moles of international terrorism and drug trafficking.

This is a battle between the forces with vested interests and self-aggrandizement on the one hand and those of nationalists supporting the uniform distribution of wealth to the benefit of entire Indian society. Their problem is a simple one. The source of loot and vandalizing of public property has been brought under check by the new agricultural laws passed by the Parliament. This law disallows the concentration of capital outside the public domain. It is a death knell to the monopolization of sources of production. ■

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भोलानाथ विज का निधन

वर्ष 1966 - 67 में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री रहे भोलानाथ विज का हृदयाघात के कारण दुःखद निधन हो गया, जिसकी जानकारी अभाविप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। अभाविप द्वारा जारी किये प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भोलानाथ विज बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे स्व. भोलानाथ विज, प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय के डीएवी महाविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बने। दिल्ली प्रदेश में विद्यार्थी परिषद में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्ष 1966 में कानपुर में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बने। इसी अधिवेशन में स्व. आचार्य गिरिराज किशोर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

वर्ष 2010 में संघ प्रेरणा से उन्होंने दिल्ली में 'चौपाल' नाम से सेवा बस्ती में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लघु ऋण उपलब्ध कराने का प्रकल्प प्रारम्भ किया। उनकी मेहनत, लगन व निष्ठा से 'चौपाल' आज हजारों परिवारों के जीवन में परिवर्तन ले आया है।

अक्टूबर में स्व. भोलानाथ को कोरोना हुआ, कोरोना को मात देकर वे ठीक हो गए थे किन्तु 16 नवंबर की रात्रि को आये हृदयाघात व 17 नवंबर को आये दूसरे हृदयाघात से भोलानाथ जी इस शरीर को छोड़ परमात्मा के चरणों मे लीन हो गए। उनका निधन समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार के लिए गहरा आघात है। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एस. सुब्बैया, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान एवं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। ■

हर दायित्व में मुझे कुछ नया सीखने को मिलाः छगन भाई पटेल

***अ**खिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गुजरात के महेसाणा नगर उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, जिला प्रमुख से लेकर गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभाने के बाद छगनभाई नानाजीभाई पटेल अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिसकी घोषणा 15 दिसंबर को की गई। अभाविप से जुड़े संस्मरण, गतिविधि, शिक्षा नीति इत्यादि सभी मुद्दों पर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' संवाददाता ने अभाविप के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की एवं उनके विचार जाने। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश –*

विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निवार्चित हुए हैं, नगर उपाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर को आप किस रूप में देखते हैं ?

संघ से तो मैं बाल्यकाल में ही जुड़ गया था लेकिन विद्यार्थी परिषद से प्रत्यक्ष रूप से वर्ष 1996 में जुड़ा। 1997 में परिषद में सबसे पहला दायित्व मुझे महेसाणा(गुजरात) नगर उपाध्यक्ष का दिया गया। बाद में, कार्य के साथ अनेक दायित्व जैसे नगर अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्व दिये गये। हर दायित्व में कुछ – न – कुछ नया सीखने को मिला। अब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, हमें लगता है इस दायित्व में भी मुझे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। विद्यार्थी परिषद में पद तो होता नहीं यहां तो दायित्व होता है।

हाल में आये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप किस प्रकार से देखते हैं ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत पहले लाना था, देर ही सही परंतु सरकार द्वारा भारत अनुकूल शिक्षा नीति लाई गई है है। इस शिक्षा नीति को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर शोध तक बिंदुवार सोच – समझकर तैयार किया गया है। विद्यालयीन शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक बुनियादी सुधार करने की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के साथ – साथ भारत की संस्कृति/स्वाभिमान को भी इसमें शामिल किया गया है। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को नौकरी लेने के बजाय देने यानी आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दी गई है।

आप सार्वजनिक फार्मेसी कॉलेज महेसाणा के प्राचार्य होने के साथ – साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। भारत में फार्मेसी क्षेत्र को लेकर आपकी क्या राय है?

भारत में फार्मा की स्थिति पहले से ही बेहतर है। मैं जहां से हूं यानी सिर्फ गुजरात से सात सौ करोड़ की दवाई ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में निर्यात हो रहा है। विश्व में ली जा रही हर तीन दवा में से एक दवा भारत की होती है। उत्पादन में भारत का विश्व स्तर पर एक तिहाई हिस्सा है लेकिन अगर खर्च (Price) के रूप में देखा जाया 1/13 वां स्थान है। इसका कारण है कि भारत की दवाईयां बहुत सस्ती होती है। कुछ दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि कोरोना काल में फार्मा सेक्टर में 96 फीसदी रिकवरी दर है।

मेडिकल उपक्रम की बात करें तो 40 प्रतिशत उत्पादन भारत से हो रहा है। एपीआई की बात करें जो मैनुफैक्चरिंग के लिए उपयोगी है, उसका रॉ मैटेरियल, इंग्रेमेडियन्स इत्यादि आज विदेश से मंगवाने पड़ते हैं। सिर्फ चीन से हम 65 प्रतिशत एपीआई मंगवाते हैं, लेकिन भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत 'लोकल फॉर वोकल' आह्वान के बाद एपीआईमें भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जल्द इस क्षेत्र में भारत अग्रणी होगा। ■

कड़कड़ाती ठंड के बीच दिन-रात 9 दिन चला अभाविप का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली उपराज्यपाल के आश्वासन के उपरांत छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल।

दिल्ली विधानसभा से मात्र दो मिनट की दूरी पर स्थित विकास भवन के सामने महात्मा गांधी रोड के फुटपाथ पर कोरोना वायरस, जानलेवा वायु प्रदूषण तथा हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच खुले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के नेतृत्व में, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सत्र में छात्रों को प्रवेश नहीं दिए जाने, दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित आईपी यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में कोरोनावायरस की मुश्किलों के बावजूद फीस बढ़ोतरी, दिल्ली सरकार के द्वारा डीयू के राज्य वित्तपोषित कॉलेजों में बढ़ते अवैध हस्तक्षेप तथा डीयू के कॉलेजों में कर्मचारियों का महीनों तक वेतन रोकने, स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड से टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन दिए जाने संबंधी गैर जिम्मेदाराना निर्णय तथा छात्रों के लिए कोरोना राहत पैकेज की मांग को लेकर छात्रों ने 9 दिनों तक प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल की।

दिल्ली सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन ने अरविंद केजरीवाल सरकार की उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता तथा लगातार हवाई किले बनाने की जुमलेबाजी की पोल खोल कर रख दी। छात्र विभिन्न मुश्किलों के बीच सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ दिन-रात डटे रहे। प्रदर्शन के बीच दिल्ली के उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने तथा इंजीनियरिंग कॉलेज को स्किल तथा एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से जोड़ने संबंधी झूठ बोलकर इस आंदोलन के बारे में लोगों को बरगलाने की असफल कोशिश भी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रचनात्मकता का आयोजन कर पोस्टर, स्लोगन, कविता पाठ, भाषण द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की सफल कोशिश की, 5 दिन तक जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के पांच छात्र भूख हड़ताल पर बैठे रहे, इसके बावजूद दिल्ली सरकार का कोई प्रतिनिधि इन छात्रों से मिलने नहीं आया, यह दिल्ली सरकार की छात्रों की समस्याओं के समाधान प्रति नकारात्मक सोच को प्रकट करने के लिए काफी

है। दिल्ली सरकार की छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीनता तथा छात्र विरोधी रवैए को देख प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुतले को ही अपना ज्ञापन सौंपा। 9 दिन तक चले प्रदर्शन में आखिरी 4 दिन छात्रों का 24 घंटे का क्रमिक उपवास रहा जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। 10 नवंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर उन्हें छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया जिसके समाधान के प्रति उपराज्यपाल ने सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना 9 दिन लंबा प्रदर्शन खत्म किया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा," अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा जी बी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के प्रदर्शन से व्यापक स्तर पर दिल्ली सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों का खुलासा हुआ है। केजरीवाल सरकार शिक्षा के मुद्दे पर अब तक केवल जुमलेबाजी तथा हवाई किले बनाने में मशगूल रही। शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर दिल्ली सरकार का अवैध हस्तक्षेप करने का तानाशाही रवैया भी जनता के सामने आया तथा उसे दिल्ली हाईकोर्ट से भी स्टूडेंट्स सोसायटी फंड से वेतन दिए जाने संबंधी निर्णय पर रोक लगाने सहित अन्य निर्णयों से लगातार झटका तथा नसीहतें मिलीं। हम लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। इस पूरे मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस सत्र को चलाने के लिए प्रतिवर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से ली जाने वाली अनुमति ही नहीं ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने हमारी विभिन्न मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा क्षेत्र में विफलता दिल्ली की जनता के बीच आ पाई, हम लोग इस प्रदर्शन के बाद सकारात्मक बदलाव को लेकर आशान्वित हैं। दिल्ली सरकार की छात्र विरोधी नीतियों तथा हवाई किले बनाने की प्रवृत्ति के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक आवाज़ भविष्य में और मुखर होगी।" ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति के लिए आशुतोष सिंह की रिपोर्ट)

अभाविप महाकौशल प्रांत द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन

प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ मिल गया है। दरअसल अभाविप महाकौशल प्रांत द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु प्रांत भर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। अभाविप कार्यकर्ता, साइकिलिंग को लोगों की दैनिक दिनचर्या से जोड़ने के लिए इस हेतु अलग – अलग स्थानों पर साइकिल चलाने का कार्यक्रम भी कर रहे हैं।

अभाविप के इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए अभाविप, महाकौशल प्रांत की प्रदेश मंत्री सुमन यादव ने कहा कि विद्यार्थी परिषद, समय-समय पर कोरोना काल में विद्यार्थियों हेतु अलग अलग आयामों के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन करता आ रहा है। इसी कड़ी में विकासार्थ विद्यार्थी(SFD) के माध्यम से जबलपुर महानगर में साइक्लोथॉन का आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचना है और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में साइकिल चलाना कितना हितकर हो सकता है। इसको लेकर के समाज में संदेश दिया गया, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर के संदेश जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। ■

अभाविप के विरोध के बाद तमिलनाडु के एमएसयू विवि ने पाठ्यक्रम से अरुंधति रॉय की पुस्तक हटायी

कन्याकुमारी : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित विभिन्न संगठनों और लोगों की शिकायत के बाद मनोनामियम सुंदरनार विश्वविद्यालय (MSU), तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) के विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रशासन ने एम.ए. अंग्रेजी के पाठ्यक्रम से लेखिका अरुंधति रॉय की पुस्तक 'वॉकिंग विद कॉमरेड्स' को हटा दिया है।

दरअसल, तीन साल पहले(2017-18) अरुंधति रॉय की पुस्तक अरुंधति रॉय की पुस्तक वॉकिंग विद कॉमरेड को तिरुनेनलवेली स्थित मनोनामियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के एम.ए. अंग्रेजी के तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। यह पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल करते ही विवाद में आ गया। अभाविप का कहना है कि उक्त पुस्तक में नक्सलियों को दिए गए हथियारों के प्रशिक्षण एवं माओवाद का महिमामंडित किया गया है।यह अत्यंत खेदजनक है कि यह पुस्तक पिछले तीन वर्षों से पाठ्यक्रम में था। इन सभी वर्षों में माओवादी विचारों और विचारधाराओं को युवा छात्रों को सिखाया गया है।

विश्वविद्यालय के कुलपति के. पिचुमणि ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, ''हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उक्त पुस्तक के बारे में शिकायत मिली थी। इसके अलावा कई अन्य लोगों से भी शिकायत मिली। हमें हमारे सिंडिकेट सदस्यों से भी शिकायत मिली है।''उन्होंने कहा कि उन शिकायतों में पुस्तक की 'विवादित' सामग्री का जिक्र है और उसे छात्रों के लिये पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की गई थी। कुलपति ने कहा कि शिकायत के बाद इसलिए मामले को लेकर वरिष्ठ शिक्षाविदों के नेतृत्व में समिति गठित की गई। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने वाले बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष भी इस समिति में शामिल थे। उन्होंने कहा, ''समिति की हुई बैठक में पुस्तक की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उसे पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला किया गया। उसके स्थान पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रकृति-प्रेमी एम. कृष्णन की पुस्तक 'माई नेटिव लैंड, एसेज ऑन नेचर' को शामिल किया गया है।''

अभाविप की दक्षिण तमिलनाडु के सह मंत्री विग्नेश ने कहा कि पिछले दिनों हमने एमएसयू के कुलपति से मुलाकात कर अरुंधति रॉय की पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की थी। क्योंकि यह पुस्तक माओवाद को महिमामंडित करती है साथ ही कई अन्य विवादित विषय शामिल हैं। यह दुख की बात है कि यह पुस्तक पिछले तीन साल से पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। इसके जरिए छात्रों पर नक्सल और माओवादी विचारधारा थोपी जा रही थी। हालांकि कुलपति ने हमारी मांगो को मानते हुए उक्त पुस्तक को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से हटा दिया है। विग्नेश ने आगे कहा कि तमिलनाडु में ऐसी ताकतें हैं, जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। हम भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपील करते हैं। ■

यह पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद है: मनीष कुमार

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार कहे जाने जाने वाले प्रा. यशवंत राव केलकर की स्मृति में दिये जाने वाले प्रा. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार 2020 हेतु जैविक कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बिहार के मनीष कुमार का चयन किया गया है। वर्ष 2020 के युवा पुरस्कार विजेता मनीष कुमार से 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के संवाददाता ने बात की और उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली । प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश –

प्रतिष्ठित प्रा. यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार 2020 के लिए आपको चुना गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें आईआईटी खड़गपुर और संघ परिवार का सर्वाधिक योगदान है। पुरस्कार तो हमें कई मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से लेकर केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी तक के हाथों सम्मानित हो चुका हूं। पिछले वर्ष आईआईटी खड़गपुर में भी मुझे श्रेष्ठ युवा पूर्ववर्ती छात्र (बेस्ट एलुमिनाई) का खिताब मिला और इस वर्ष 2020 के युवा पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया, मेरे लिए यह भावुक पल है। यह पुरस्कार मेरे लिए यह अवार्ड नहीं आशीर्वाद है क्योंकि जिस विचार/परिवार ने आपको पहचान दी और वही आपको सम्मान दे तो वह पुरस्कार नहीं आशीर्वाद होता है।

आप अपने कार्यों के बारे में बताये ?

पिछले दस वर्षों से मैं कृषि क्षेत्र में काम कर रहा हूं। प्रारंभिक पांच वर्ष हमने अपने गृह राज्य बिहार में काम किये, जिसकी शुरूआत अपने गांव से की और एक संगठन बनाई जो बाद के समय में काफी बड़ी हुई है। वर्तमान में यह 800 करोड़ की है। 2016 में मुझे लगा कि हमें जैविक कृषि पर ही काम करना चाहिए। यह बेहद कठिन फैसला था मेरे लिए कि अपने ही बनाई कंपनी को छोड़कर नया कार्य शुरू करना। फिर मैंने इसे छोड़ दिया। कई लोगों ने मुझे मना किया ऐसा क्यों कर रहे हो? व्यवस्थित संगठन को छोड़ रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि पैसा कमाना तो कभी मेरा लक्ष्य रहा ही नहीं। इस तरह हमने पुराने संगठन को पांच वर्ष पहले छोड़ दिया। नया संगठन 'बैक टू विलेज' बनाया, व्यवस्थित

संगठन को छोड़कर नया संगठन बनाकर काम करना कठिन था लेकिन धीरे – धीरे सब ठीक हो गया। बैक टू विलेज पूर्णतः जैविक कृषि पर आधारित जो खुशहाल उपभोक्ता – समृद्ध किसान को ध्येय वाक्य मान कर कार्य कर रही है।हमलोग किसानों को जैविक कृषि हेतु वैज्ञानिक पक्ष से उसकी भाषा में परिचित करा कर जैविक कृषि को बढ़ाने और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए अलग – अलग जगहों केन्द्र बनाया है जिसे उन्नत कृषि केन्द्र कहते हैं। उन्नत कृषि केन्द्र के लिए हमलोगों ने एक मॉडल विकसित किया है जिसके लिए गांव के ही युवा किसान को प्रशिक्षित करते हैं और वे किसानों की उपादेयता के अनुरूप के क्रय – विक्रय कराना, बीज देना, प्रशिक्षण देना इत्यादि का काम करता है।वर्तमान में यह तीन राज्यों में चल रहा है, जिसमें छः हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ाई करने के बाद आपको तो बड़ी – बड़ी कंपनियों से अच्छी – खासी पैकेज वाली नौकरी के लिए ऑफर आया गया होगा फिर भी आपने कृषि क्षेत्र को ही क्यों चुना?

हम जो कार्य कर रहे हैं, वह बेहद समान्य है। 2010 में जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई कर रहा था तभी मुझे भारत रत्न नानाजी देशमुख के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना, शायद उसी समय उनका देहावसान हुआ था। नाना जी के कार्यों से मैं काफी प्रभावित हुआ और इस कार्य के दृढ़ संकल्पित हुआ। नाना जी हमारे आदर्श हैं और उनका कहना था कि हमें दूसरो के लिए जीना चाहिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमने देश को परिवार मानकर गांव में जाकर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। ■

नहीं रहे अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओह्वाल, कार्यकर्ताओं में शोक की लहर

नवंबर में जहां दुनिया गुनगुने धूप का आनंद ले रही थी वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर दुख के घने बादल छाए हुए थे। दरअसल 11 नवंबर को अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओह्वाल का महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की धड़गांव तहसील में नदी में डूबने से दुखद निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार गहन दुख तथा पीड़ा में है। इस घटना की जानकारी अभाविप के केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्री ने कहा है कि दुख तथा पीड़ा भरे इस कठिन समय में सम्पूर्ण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार, श्री अनिकेत ओह्वाल के परिवार के साथ है तथा उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता है

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री अनिकेत ओह्वाल मुंबई के रहने वाले हैं। प्रतिष्ठित रुईया महाविद्यालय से एमएससी की शिक्षा पूर्ण करने वाले महाराष्ट्र में छात्र आन्दोलन के सशक्त छात्रनेता अनिकेत ओव्हाल ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक छात्र आंदोलनों के माध्यम से छात्रों के हितों की रक्षा हेतु महती भूमिका निभाई। वे अभाविप के समर्पित छात्र कार्यकर्ता थे जो निरंतर छात्रों के कल्याण हेतु प्रयासरत रहे। कोरोना संक्रमण काल में भी निष्ठापूर्वक सेवा कार्यों में अग्रसर रहे। उनका असामयिक निधन समस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। ।■

भगवान बिरसा को अभाविप ने जनजाति गौरव के रूप में किया याद, देश भर में कार्यक्रम का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 नवंबर भगवान बिरसा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। विद्यार्थी परिषद ने बिरसा जयंती पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये। अभाविप महाराष्ट्र के द्वारा जलगांव के द्वारा वेब संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी में अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिक्षाविद मिलिंद मराठे ने कहा कि भगवान बिरसा का जीवन अनुकरणीय है। अंग्रेजों के सामने झूकने के बजाय उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया। वे समस्त भारतीयों के गौरव हैं।

भगवान बिरसा की जन्मस्थली झारखंड राज्य के खूंटी में जनजाति गौरव दिवस के मौके पर पांच दिवसीय बिरसा मुंडा हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट के में प्रथम स्थान लाने वाले विजेता आर. डी. खूंटी टीम को 33000 रुपया नगद इनाम एवं अम्बाटोली टीम को द्वितीय स्थान को 11000 रुपया नगद इनाम दिया गया।वहीं रांची स्थित बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार में अभाविप द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने कारागार में भगवान बिरसा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किये एवं उनके पदचिह्नों पर चलने का संकल्प लिया।

कटकल गोंदा बस्ती में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभाविप के प्रांत अध्यक्ष नाथु गाड़ी ने कहा कि कि अभाविप भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है और हम सभी अभाविप के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव जा जाकर ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को सफल बना कर सभी ग्रामीण को भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी को बताने का काम करेगें। उन्होंने कहा कि जनजातीय होने पर हम सभी को गर्व है।

अभाविप प्रांत जनजातीय कार्य प्रमुख सोमनाथ भगत ने संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए कहा कि आज के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज और देश के लिए आगे आने की जरूरत है।अभी समाज और देश को असामाजिक तत्वों से जनजाति समाज के लोगों को कई प्रकार के खतरे हैं बिरसा मुंडा की बलिदानी आजाद भारत में व्यर्थ नहीं जाएगी। षड्यंत्रकारी जो समाज व देश को तोड़ने की विचार करते हैं उनका सपना कभी हम सभी जनजाति समाज के लोग कभी साकार नहीं होने देंगे। वहीं कटहल गोंदा के पाहन साधना मुंडा ने कहा है की जल - जंगल - जमीन हमारा है। जिसे भगवान बिरसा मुंडा जी ने बचाया है। भगवान बिरसा मुंडा जिस प्रकार अपनी माटी के रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। इसे हम सभी को सीख लेकर उनके सिखाए गए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार मिशनरियों के खिलाफ लड़ा यह भी हम सभी को सीखने की आवश्यकता है।कार्यक्रम के मंच संचालन रोमा तिर्की व बरखा कुजूर ने किया। मौके पर बस्ती वालों का उत्साह चरम पर था। ■

ग्वालियर: विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली छात्राओं को अभाविप ने किया सम्मानित

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 192 वीं जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ग्वालियर में सम्मान समारोह को आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली 192 छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लगातार छात्राओं के विकास के लिए काम करती है। "मिशन साहसी" के अंतर्गत अभाविप ने महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें उनके साथ हो रही छेड़छाड़ के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी, इसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से 1.2 मिलियन लड़कियों को प्रशिक्षण दिया। इस मिशन की खास बात यह है कि पूरे मिशन का आयोजन लड़कियों द्वारा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि समाज उन क्षेत्रों का मार्गदर्शन करें जिनमें महिलाएं जाना चाहती हैं, न कि उनके लिए बाधा बनें।

लक्ष्मी बाई हमेशा समाज के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। इस आधुनिक समय में, लक्ष्मी बाई जी के विचार आज भी सभी को प्रेरणा देती हैं। अभाविप ने इसी बातों को ध्यान में रखकर 21 नवंबर को को 192 उन महिलाओं और छात्राओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में समाज की प्रगति के लिए काम किया है और साबित किया है कि भारतीय समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई अंतर नहीं है, इसमें विभिन्न श्रेणियां जैसे शैक्षिक, नेतृत्व, पुलिस, डॉक्टर्स, कोविड वॉरियर, खेल, कला, संस्कृति, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, और समाज के सभी वर्गों की महिलाएं और लड़कियां शामिल किया। इससे समाज के लिए एक संदेश भी दिया है, "192 वीं जयंती पर अभाविप ग्वालियर ने 192 महिलाओं और लड़कियों को सम्मानित किया।"

विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान देने वाले छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। निधि त्रिपाठी इस सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि थीं। इसके अलावा नीलेश सोलंकी(प्रदेश मंत्री, मध्यभारत अभाविप)और प्रमिला वाजपेयी (पूर्व सदस्य राज्य महिला)आयोग द्वारा भी सम्मानित किया गया। इस समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह थीं कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन अभाविप ग्वालियर के छात्रा कार्यकर्ताओं द्वारा द्वारा किया गया था, जो दर्शाता है कि महिलाएं कुछ भी करने में समान रूप से सक्षम हैं। ■

स्त्री शक्ति दिवस की झलकियां

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 DECEMBER, 2020
DATE OF PUBLISHING: 8 DECEMBER, 2020
POSTAL REGD. NO.: DL(C)-11/1409/2020-2022
POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI